वर्ष- चार, अंक- 10 जनवरी- 2025 मूल्यः 20

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

नवजीवन संदेश

भारत के 76 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली. इस बार समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो रहे. इस मौके पर देश की राष्ट्रपति और भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली. यह दिलचस्प है कि भारत ने जब अपना पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया था, तब उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो थे.

RNI No : JHAHIN/2021/83133

बीसीसीएल
BCCL
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
Bharat Coking Coal Limited

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनीरत्न कम्पनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड का एक अंग)

गणतंत्र दिवस

26 जनवरी

के शुभ अवसर पर बीसीसीएल परिवार
की ओर से सभी देशवासियों को

हार्दिक शुभकामनाएं

कोकिंग कोयला से राष्ट्र के विकास को गति देता बीसीसीएल

- नई तकनीकों के समावेश से राष्ट्र की प्रगति में योगदान
- विविधीकरण और स्थिरता की ओर बढ़ते कदम
- सामाजिक सरोकारों के प्रति सदैव समर्पित
- पर्यावरण संरक्षण हमारी प्रतिबद्धता

कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद

FACEBOOK/BCCLOFFICIAL TWITTER/BCCLOFFICIAL
INSTAGRAM/BCCL.OFFICIAL

index

RNI No: JHAHIN/2021/83133

अनुमानों पर आधारित है श्रद्धालुओं की संख्या पेज-21

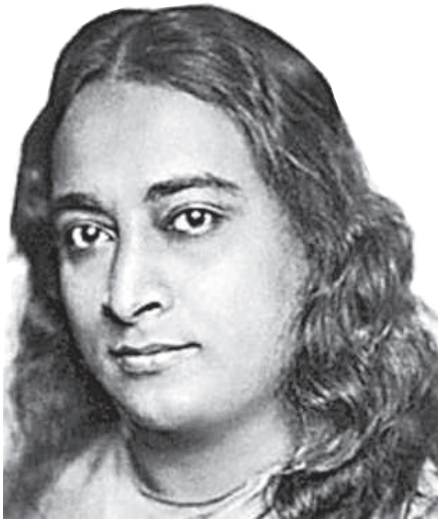

श्री श्री परमहंस योगानन्द की स्थायी विरासत पेज-30

राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने किए कई विवादास्पद ऐलान पेज-11

नवजीवन संदेश
राष्ट्रीय मासिक पत्रिका
Web : navjeewansandesh|com
संबद्धता : प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (भाषा)
▪ वर्ष -4, ▪ अंक -10, ▪ कुल पृष्ठ -36

प्रधान संपादक
पंकज कुमार सिंह

संपादक
प्रभात मजुमदार

संपादक मंडल
जगन्नाथ मुंडा
सुनीता सिन्हा
श्रीमती छाया
रविप्रकाश

खेल डेस्क प्रभारी
चंचल भट्टाचार्य

छायाकार
नसीम अख्तर

संपर्क : 9431708799
9835437102
ईमेलः navjeewansandesh@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक और प्रकाशक पंकज कुमार सिंह द्वारा प्रथम तल, होटल आलोका कॉम्प्लेक्स रेडियम रोड, समीप कचहरी चौक, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित तथा मैसर्स डी।,बी। कॉर्प लि। प्लॉट नंबर 535 व 1272, लालगुटवा, पुलिस स्टेशन रातू रांची से मुद्रित।
संपादक : प्रभात मजुमदार* (*संपादक इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पीआरबी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी)
आरएनआई नं।: JHAHIN/2021/83133

संपादकीय

ऐतिहासिक उपलब्धि

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 16 जनवरी को 'स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट' के तहत उपग्रहों की 'डॉकिंग' में सफलता हासिल की है. क्या होती है डॉकिंग और भारत के लिए यह जरूरी क्यों है?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 16 जनवरी को 'स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट' (स्पेडेक्स) के तहत उपग्रहों की 'डॉकिंग' करने में सफल हुआ. भारत ने यह मिशन पूरा करके शून्य गुरुत्वाकर्षण में जटिल तकनीकी उपलब्धि हासिल की है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद इसरो ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर अपने हैंडल से पोस्ट शेयर किया "भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है. इस क्षण का गवाह बनकर गर्व महसूस हो रहा है."

यह बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले केवल अमेरिका, चीन और रूस ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग कर पाए हैं. अब भारत ने भी इस छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण फेहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

डॉकिंग एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें उपग्रहों को आगे-पीछे ले जाया जाता है जिसे इसरो ने अंतरिक्ष में दो उपग्रहों के "रोमांचक हैंडशेक" के रूप में वर्णित किया है.

इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया था. डॉकिंग तकनीक तब आवश्यक होती है जब सामान्य मिशन के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने की जरूरत होती है. इसके पहले 12 जनवरी को इसरो ने डॉकिंग का ट्रायल किया था क्योंकि इस कठिन प्रक्रिया में कई ट्रायल यानी कि कोशिशें लग जाती हैं.

इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान-4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन निर्भर थे. चंद्रयान-4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे, वहीं गगनयान मिशन में इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा.

इसरो के लिए इस मिशन का सफल होने बहुत जरूरी था. दरअसल इसका उपयोग उपग्रहों की सर्विसिंग, अंतरिक्ष स्टेशन संचालन और ग्रहों के बीच आपस में चल रहे मिशनों में होता है. भारत की सफल उपग्रह डॉकिंग अंतरिक्ष में छिपे कई और रहस्य और जानकारी के लेन-देन में बहुत काम आएगी.

इसरो ने पीएसएलवी सी 60 रॉकेट से इन उपग्रहों को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया. रॉकेट ने उड़ान भरने के करीब 15 मिनट बाद लगभग 220 किलोग्राम वजन वाले दो छोटे अंतरिक्ष यानों को 475 किलोमीटर की कक्षा में प्रोजेक्ट किया.

तकनीकी दक्षता के साथ साथ इस मिशन के जरिए भारत वैश्विक कमर्शियल अंतरिक्ष मार्केट में अपनी जगह सुनिश्चित कर रहा है. 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, फिलहाल भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% या 8 बिलियन डॉलर है. सरकार का लक्ष्य 2040 तक इसे बढ़ाकर 44 बिलियन डॉलर करना है.भारत का ये मिशन ना केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती स्थिति को दिखाता है बल्कि ये देश की भविष्य की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान करता है.

राजधानी में राज्यपाल, उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री ने फहराया तिरंगा, कहा

हर वर्ग के लिए काम कर रही है सरकार, महिला सशक्तिकरण पहली प्राथमिकता

76 वें गणतंत्र दिवस पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार ने झंडोत्तोलन किया। वहीं उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर बात रखी। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को खुशहाल बनाने एवं प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ अपने इस कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। उन्होंने नक्सली अभियानों में मिली उपलब्धियों की सराहना की। राज्य सरकार बदलते भविष्य को देखते हुए काम कर रही है। कृषि हमारे प्रदेश के विकास का मूल आधार है। अन्नदाता किसानों को खेती किसानी की सभी संभव सुविधाएं और उनके उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार संकल्पित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसे अनेक पहलुओं के माध्यम से किसानों के कल्याण के लिए काम किया जा रहे हैं।

इस वित्तीय वर्ष में 1.82 लाख लाभुकों का 403 करोड़ का ऋण माफ किया गया है। बिरसा फसल विस्तार योजना अंतर्गत खरीफ एवं रबी के पूर्ण अनुदान पर गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण किसानों के बीच किया गया है। वहीं मनरेगा के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 7.4 करोड़ मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 2430 करोड़ की राशि व्यय की गई है। इसके तहत 2.9 लाख योजनाओं को पूरा किया जा चुका है।

राज्य सरकार की अन्य योजनाओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और राज्य सरकार के कार्यों की तारीफ की। श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण, कौशल विकास, विश्वविद्यालय में पढ़ाई आदि पर भी राज्यपाल ने जोर देते हुए सरकार के कार्यों की तारीफ की।

गणतंत्र दिवस पर झारखंड की उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली। सोरेन ने कहा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी झारखंड के कई आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र थे, जहां आजादी की लड़ाई लड़ी गई। झारखंड के ऐसे महान विभूतियों भगवान बिरसा मुण्डा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव, बहन फूलो-झानो, वीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, शेख भिखारी, टिकैत उमरांव सिंह, पाण्डेय गणपत राय, शहीद विष्वनाथ शाहदेव को भी नमन करता हूं। उनकी संघर्ष गाथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

उन्होंने कहा राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सत्ताधारी दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, वह भी दो तिहाई बहुमत के प्रचंड जन-समर्थन के साथ। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय, विशेषकर हमारी माताओं-बहनों ने जो भरोसा और विश्वास जताया है, अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। कहा कि आपके भरोसे ने हमारी जिम्मेवारियां और बढ़ा दी हैं। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम दोगुने उत्साह से काम कर रहे हैं।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। आज से लगभग पांच महीने पहले हमारी सरकार ने बहनों-दीदियों की आर्थिक स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य से मंईयां सम्मान योजना के रूप में एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की थी। क्रांतिकारी इसलिए, क्योंकि राज्य की सामाजिक- आर्थिक पृष्ठभूमि एवं ग्रामीण परिवेश में यह योजना व्यापक बदलाव लाने का सामर्थ्य रखती है। मंईया सम्मान योजना हमारी बहनों, दीदियों के चेहरे पर खुशी की गारंटी बन गई है।

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के से 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। फुलो झानो आशीर्वाद योजना, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना के माध्यम से महिलाओं को आजीविका का सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। पलाश ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिला है।

राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 48 हजार पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसमें से 46 हजार पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। इनमें से 5 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा 28 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं-13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरणों में है, जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षाफल प्रकाशित किये जायेंगे। हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि नियुक्तियों में झारखंड के लोगों को उनका उचित हक मिले। हेमंत सोरेन ने कहा कि जो युवा स्वरोजगार करना चाहते हैं उन्हें आर्थिक मद्द उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 7,625 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं और लाभुकों के बीच 438 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है।

सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के हर जरूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अबुआ आवास योजना के माध्यम से गरीबों को तीन कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना तथा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभ दिए जा रहे हैं।

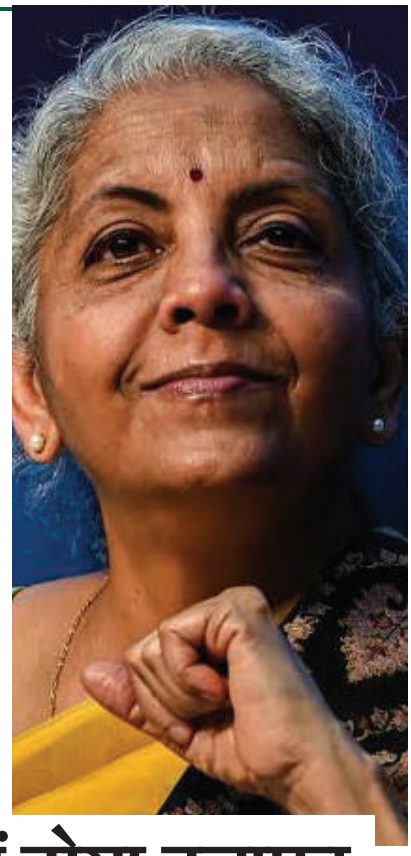

8 वें वेतन आयोग को मंजूरी; सैलरी में होगा इजाफा

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक एक साल पहले ही ये फैसला ले लिया गया। सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है।

बता दें, 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं, और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ''प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी।'' मंत्री ने कहा कि 2025 में नये वेतन आयोग के गठन से यह सुनिश्चित होगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य पक्षों के साथ परामर्श किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस कदम से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मियों को लाभ होगा। साथ ही लगभग 65 लाख पेंशनधारकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इससे दिल्ली के लगभग चार लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। (आमतौर पर, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ वृद्धि होती है।) इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ उपभोग और आर्थिक वृद्धि को महत्वपूर्ण गति मिलेगी।

> केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ''प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी।'' मंत्री ने कहा कि 2025 में नये वेतन आयोग के गठन से यह सुनिश्चित होगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं।

क्या होता है वेतन आयोग

सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में एक आयोग का गठन करती है, जो मुद्रास्फीति के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के वेतन याने बेसिक सैलरी, भत्तों को बढ़ाने की अनुशंसा करता है। वेतन आयोग की सिफारिशों पर ही सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में परिवर्तन करती है।

वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है। पिछले कुछ वेतन आयोगों, खासकर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में खासी बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते युवाओं में एक बार फिर सरकारी नौकरियों को लेकर उत्साह देखा गया। इससे कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी करने की इच्छा रखने वाला टेलेंट, सरकारी सेवा में आना शुरु हुआ। जिसका कारण सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी के साथ-साथ वेतन भी निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के समतुल्य होता दिखा।

अभी लागू है 7वां वेतन आयोग

वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन वृद्धि मिलती है। 7वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का मासिक वेतन 18 हजार रुपये से लेकर ढाई लाख रुपये तक करने की सिफारिश की थी। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 को खत्म हो जाएगा। सातवें वेतन आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। सरकार ने 1947 के बाद से सात वेतन आयोग का गठन किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकारों के स्वामित्व में आने वाली ज्यादातर इकाइयां आयोग की सिफारिशों का अनुकरण करती हैं।

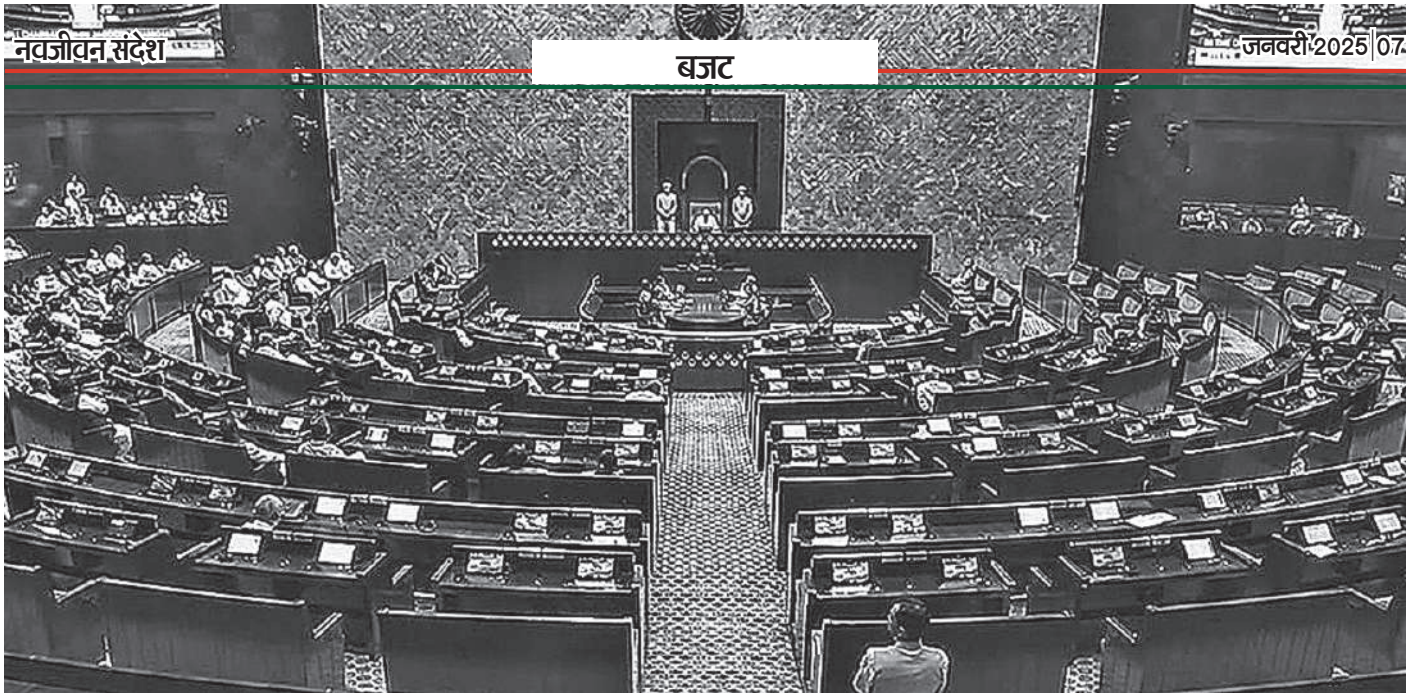

31 जनवरी से शुरू होगा संसद सत्र, एक को पेश होगा बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाएंगी नए रिकॉर्ड

▪ चारु कार्तिकेय

सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल को समाप्त होगा। इस दौरान संसद की स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों के बजट आवंटन की जांच करेंगी।

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में अभिभाषण से शुरू होगा, इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले दिन 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण का यह लगातार आठवां बजट होगा।

सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल को समाप्त होगा। इस दौरान संसद की स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों के बजट आवंटन की जांच करेंगी।

सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कुल 27 बैठकें होंगी। यह सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पारंपरिक अभिभाषण से शुरू होगा, उसके बाद सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेगी। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जो शनिवार को पड़ रहा है, इसके बाद दोनों सदन 3 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, बीएसई और एनएसई 1 फरवरी 2025 को शनिवार होने के बावजूद खुले रहेंगे, क्योंकि उस दिन केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया जाएगा। एक्सचेंज ने एक प्रेस नोट में कहा, "केंद्रीय बजट के चलते, एक्सचेंज 1 फरवरी 2025 को एक लाइव ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेगा।" बता दें कि भारतीय शेयर बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं।

निर्मला सीतारमण बनाएंगी रिकॉर्ड

इस बजट के साथ ही निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार आठ बजट पेश करने का रिकॉर्ड बना रही हैं। जुलाई में जब उन्होंने लोकसभा चुनावों के बाद बजट पेश किया था, तब उन्होंने 68 साल पहले सी.डी. देशमुख द्वारा हासिल की गई उपलब्धि की बराबर की थी। देशमुख, जिन्होंने 1951 से 1956 तक बजट पेश किए, और निर्मला दोनों ने छह पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था।

देशमुख के दो बजट 1952 में पहले लोकसभा के गठन से पहले के थे। अगर हम लगातार पूर्ण बजट की बात करें, तो निर्मला पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी, जिन्होंने कांग्रेस सरकारों में छह लगातार बजट पेश किए थे। अगर वह कम से कम मार्च 2028 तक वित्त मंत्री बनी रहती हैं, तो वह 11 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी, जो अब तक किसी ने नहीं किया है।

फिलहाल, मोरारजी का रिकॉर्ड 10 है, इसके बाद पी. चिदंबरम (9) और प्रणब मुखर्जी (8) हैं, साथ ही देशमुख और निर्मला (7-7) भी शामिल हैं। मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा, चिदंबरम, मुखर्जी और अरुण जेटली ने पांच लगातार बजट पेश किए हैं।

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए केंद्र व राज्य को मिलकर करना होगा कार्य

झारखंड की राजधानी रांची के अध्ययन भ्रमण पर आए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु गठित सात सदस्यीय संसदीय समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले इस संसदीय समिति के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य डॉ फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ सदस्य डॉ मल्लू रवि (लोकसभा सांसद), श्री वीडी राम (लोकसभा सांसद), श्रीमती प्रतिमा मंडल (लोकसभा सांसद), श्री रवांग्वरा नारज़ारी (राज्यसभा सांसद), श्रीमती फूलो देवी नेताम (राज्यसभा सांसद) और श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह (राज्यसभा सांसद) शामिल थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं संसदीय समिति के बीच अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं समेत कई विषयों/मुद्दों पर विस्तृत विचार- विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान और विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, जहाँ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की एक बड़ी आबादी निवास करती है, लेकिन प्रगति के रास्ते पर उन्हें जितना आगे आना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। ऐसे मे विकास में उनकी भागीदारी मजबूत करने के

लिए ठोस नीति बनाकर उसे योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना होगा ताकि उन्हें सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य करती आ रही है और उसके सकारात्मक परिणाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। हमारी सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है और विजन डाक्यूमेंट तथा रोड मैप तैयार कर आगे कई और ठोस कदम उठाने जा रही है।

मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात करने वाले संसदीय समिति के सचिव एवं एडिशनल सेक्रेटरी श्री डी आर शेखर, डिप्टी सेक्रेटरी श्री मोहन अरुमाला, अंडर सेक्रेटरी श्री एन टूथांग,जॉइंट डायरेक्टर श्री टीआरएस गोस्वामी तथा कमिटी अफसर श्रीमती पूजा किर्थवाल भी शामिल थे।

रांची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष आदरणीय डॉ फग्गन सिंह कुलस्ते जी एवं समिति के अन्य सदस्यों के साथ मुलाकात हुई। तथा मुलाकात के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं समेत कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य को मिलकर कार्य करना होगा। हमारी सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विजन डाक्यूमेंट तथा रोड मैप तैयार कर हम आगे कई और ठोस कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड

झारखंड विस सत्र- तीन मार्च को पेश होगा बजट

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से प्रारंभ होगा, राज्यपाल संतोष गंगवार ने सत्र को मंजूरी दे दी है। 24 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र के पहले दिन नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के अलावा राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रकाश का कार्यक्रम है। बजट सत्र के पहले दिन 24 फरवरी को साढ़े ग्यारह बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। देश की दिवंगत विभूतियों को इस दिन याद कर श्रद्धांजलि देने के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। बजट सत्र में कुल 20 कार्य दिवस निर्धारित हैं।

3 मार्च को पेश होगा बजट : राज्यपाल के अभिभाषण पर दूसरे दिन 25 फरवरी और तीसरे दिन 27 फरवरी को वाद-विवाद के साथ सरकार का उत्तर होगा। 26 फरवरी को अवकाश रहेगा। 28 फरवरी को सरकार चालू वित्त वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। तीन मार्च को प्रश्नकाल के बाद वित्त वर्ष 2025-26 का बजट हेमंत सरकार पेश करेगी। सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे।

बजट सत्र का पूरा शेड्यूल

- **24 फरवरी** : नए सदस्यों की शपथ, राज्यपाल का अभिभाषण, शोक प्रकाश
- **25 फरवरी**: प्रश्नकाल, राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद
- **26 फरवरी** : अवकाश
- **27 फरवरी** : प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष 2024-25 का तीसरा अनुपूरक बजट, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, सरकार का उत्तर
- **28 फरवरी** : प्रश्नकाल, अनुपूरक पर चर्चा
- **01 से 02 मार्च** : अवकाश
- **03 मार्च** : वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट
- **04 से 07 मार्च**: प्रश्नकाल, बजट पर वाद-विवाद
- **08 से 09 मार्च**: अवकाश
- **10 से 11 मार्च**: प्रश्नकाल, बजट पर वाद-विवाद
- **12 से 16 मार्च तक** : अवकाश
- **17 से 21 मार्च**: प्रश्नकाल, बजट पर वाद-विवाद
- **22-23 मार्च**: अवकाश
- **24 मार्च**: प्रश्नकाल, बजट पर वाद-विवाद, विनियोग विधेयक
- **25 मार्च**: प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक
- **26 मार्च**: प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक व अन्य राजकीय कार्य
- **27 मार्च**: प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक, गैर सरकारी संकल्प

भाजपा मुख्यालय के करीब होगा कांग्रेस मुख्यालय

▪ समीरात्मज मिश्र

यह पता है भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। लेकिन 15 जनवरी से यह पता बदल गया और कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय होगा 9ए कोटला रोड, नई दिल्ली। पार्टी ने मुख्यालय के छह मंजिला इस नए भवन का नाम रखा है इंदिरा गांधी भवन।

"15 जनवरी, 2025 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने नए एआईसीसी मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन का उद्घाटन किया। इस इमारत का निर्माण तभी शुरू हुआ था जब सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष थीं। 9ए कोटला मार्ग पर इंदिरा गांधी भवन को पार्टी और उसके नेताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।"

इस नये परिसर में कांग्रेस के विभिन्न फ्रंटल संगठन, जैसे- महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के भी दफ्तर स्थानांतरित किए जाएंगे। अब 26 अकबर रोड पर बने कांग्रेस सेवा दल के दफ्तर और 5 रायसीना रोड पर बने एनएसयूआई के दफ्तर को भी इसी नए इंदिरा भवन में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा।

कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर की इस इमारत का शिलान्यास साल 2009 में तब हुआ था जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी थीं। लेकिन इसके निर्माण में 15 साल क्यों लग गए, यह भी बड़ा सवाल है। इस देरी की मुख्य वजह संसाधनों की कमी को बताया जा रहा है, ये अलग बात है कि 2009-2014 तक केंद्र में यूपीए सरकार थी और तमाम राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं।

करीब पांच दशक पुराने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का पता अब बदल जाएगा. दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के ही पास अब कांग्रेस मुख्यालय बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 15 जनवरी को हुआ.

कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की इस नई इमारत का पता 9ए कोटला मार्ग जरूर है लेकिन इसे जमीन का आवंटन उसी दीनदयाल मार्ग पर हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, लेकिन पार्टी ने अपने मुख्य प्रवेश द्वार को कोटला मार्ग पर बनाया है ताकि दफ्तर का पता यही रहे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय साल 2018 में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनी नई इमारत में शिफ्ट हुआ था जो कि एक आलीशान और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। बीजेपी का मुख्य द्वार दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर खुलेगा, जिसका पता 6, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग है जबकि कांग्रेस ने तय किया है कि उसका मुख्य द्वार कोटला रोड पर होगा और उसका पता होगा 9ए, कोटला रोड।

वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को कवर करते रहे हैं और कांग्रेस के इतिहास पर लिखते रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही अपने मुख्यालय का दफ्तर चाहते थे क्योंकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर भी यहीं है, लेकिन बीजेपी का मुख्यालय यहां पहले बन गया और आरएसएस से जुड़े तमाम संगठनों के दफ्तर भी इसी रोड पर हैं इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कोटला रोड को अपना नया पता बनाया है।

अरविंद कुमार सिंह कहते हैं, "दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर पहले से यहां था इसलिए पार्टी के लोग मुख्यालय भी यहां बनाना चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब अनंत कुमार शहरी विकास मंत्री थे, तब इस रोड पर आरएसएस के संगठनों को 22 दफ्तर आवंटित कर दिए गए थे। एक तरह से उस जगह को बीजेपी ने तभी से आरक्षित कर लिया था। फिर जब साल 2009 में पार्टियों के लिए जगह का आवंटन हुआ तो बीजेपी को भी वहीं जमीन मिल गई दफ्तर बनाने के लिए। हालांकि नेहरू के समय जब कांग्रेस पार्टी के लिए नई दिल्ली में दफ्तर की जगह तलाश की जा रही थी तब इसी जगह को प्राथमिकता दी गई थी। इसका बड़ा कारण

इंदिरा गांधी भवन

यह था कि यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक है और उस समय दूर-दराज से आने वाले ज्यादातर लोग ट्रेन से ही आते-जाते थे।"

24 अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर 1978 में उस वक्त शिफ्ट हुआ था जब पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी लोकसभा का चुनाव हार गई थी और तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे। साल 1977 में इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी हार गई तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर टूट गई। उन्हीं परिस्थितियों में इंदिरा गांधी ने जनवरी 1978 में पार्टी के दफ्तर को यहां शिफ्ट किया। ये दिल्ली के लुटियंस इलाके का टाइप 7 बंगला था, जो उस वक्त आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सांसद जी वेंकटस्वामी के नाम पर आवंटित था।

24 अकबर रोड का यह बंगला उससे पहले भी काफी अहम जगह हुआ करती थी। इंडियन एयरफोर्स के चीफ का घर होने के अलावा यहां इंटेलिजेंस ब्यूरो की पॉलिटिकल सर्विलांस विंग का ऑफिस भी हुआ करता था और उससे भी पहले इसे बर्मा हाउस के नाम से जाना जाता था। इस घर का यह नाम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिया था क्योंकि इसी बंगले में म्यांमार की भारत में राजदूत डॉक्टर खिन काई अपनी बेटी आंग सान सू ची के साथ रहने आईं थीं।

लेकिन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के लिए इस बंगले का चुनाव करने के पीछे एक कारण यह भी था कि इसी से जुड़ा हुआ 10 जनपथ का भी बंगला है जो उस वक्त इंडियन यूथ कांग्रेस का दफ्तर हुआ करता था। यही 10 जनपथ बाद में सोनिया गांधी का आवास बना और अभी भी यह उनका आवास है।

24 अकबर रोड को कांग्रेस का मुख्यालय भले ही विपरीत परिस्थितियों में बनाया गया था लेकिन यह इमारत कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी के लिए काफी भाग्यशाली साबित हुई क्योंकि 1980 के चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सत्ता में फिर वापसी हुई। यह दफ्तर देश के चार प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के अलावा सात पार्टी अध्यक्षों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यकाल का गवाह रह चुका है।

वैसे दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का पहला दफ्तर जंतर-मंतर रोड पर था। अरविंद कुमार सिंह बाते हैं, "आजादी के बाद कांग्रेस ने अपना दफ्तर जब इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट किया तो यह नया मुख्यालय 7 जंतर-मंतर रोड था। यह भवन साल 1969 तक कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा। लेकिन 1969 में कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बंट गई और फिर दफ्तर भी यहां से चला गया। हुआ यह कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने और वीवी गिरी के राष्ट्रपति चुने जाने के मुद्दे पर इंदिरा गांधी और कांग्रेस के पुराने नेताओं के बीच जबरदस्त विवाद हुआ और यह विवाद इतना बढ़ा कि पार्टी ही दो हिस्सों में टूट गई। पुराने नेताओं की पार्टी हुई कांग्रेस (ओ), जिसका मुख्यालय 7 जंतर-मंतर ही रहा जबकि इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी का नाम रखा कांग्रेस (आर)। अब इंदिरा गांधी को एक नए दफ्तर की जरूरत थी। तो कांग्रेस के पुराने नेता और नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य रहे एमवी कृष्णप्पा के घर विंडसर प्लेस को इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया।"

साल 1971 में पार्टी का दफ्तर 5 राजेंद्र प्रसाद रोड पर शिफ्ट हो गया और लेकिन साल 1977 में इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी में एक बार और टूट हुई तो इंदिरा गांधी ने जनवरी 1978 में पार्टी मुख्यालय को 24 अकबर रोड पर शिफ्ट कर दिया और तब से लेकर यह अब तक पार्टी का मुख्यालय है।

हालांकि कांग्रेस पार्टी का पहला दफ्तर तो इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू का घर ही था जो स्वराज भवन के रूप में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा। मोतीलाल नेहरू जाने-माने वकील और कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने इलाहाबाद के चर्चलेन में एक बड़ा बंगला बनवाया जिसका नाम आनंद भवन रखा। कांग्रेस के नेताओं का उस घर में आना-जाना रहा और एक तरह से वह राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का एक केंद्र बन गया। साल 1930 में मोतीलाल नेहरू ने उसके पास में ही एक और घर बनवाया। अब पुराने घर का नाम बदलकर स्वराज भवन कर दिया गया और जो नया घर बना उसे आनंद भवन का नाम दिया गया। स्वराज भवन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होने लगा और आनंद भवन में नेहरू परिवार रहने लगा।

अरविंद कुमार सिंह बताते हैं, "नमक सत्याग्रह के दौरान मोतीलाल नेहरू ने यह बंगला गांधी जी को समर्पित कर दिया था। आजादी के आंदोलन के दौरान यही स्वराज भवन कांग्रेस का मुख्यालय रहा और कांग्रेस वर्किंग कमिटी की तमाम बैठकें यहीं होती रहीं। देश की आजादी तक यही कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा। यही नहीं, राममनोहर लोहिया, जेबी कृपलानी जैसे तमाम नेता यहां लंबे समय तक रहे भी। स्वराज भवन में आजादी के इतिहास के एक बड़े और महत्वपूर्ण कालखंड को समेटे हुए है।"

राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने किए कई विवादास्पद ऐलान

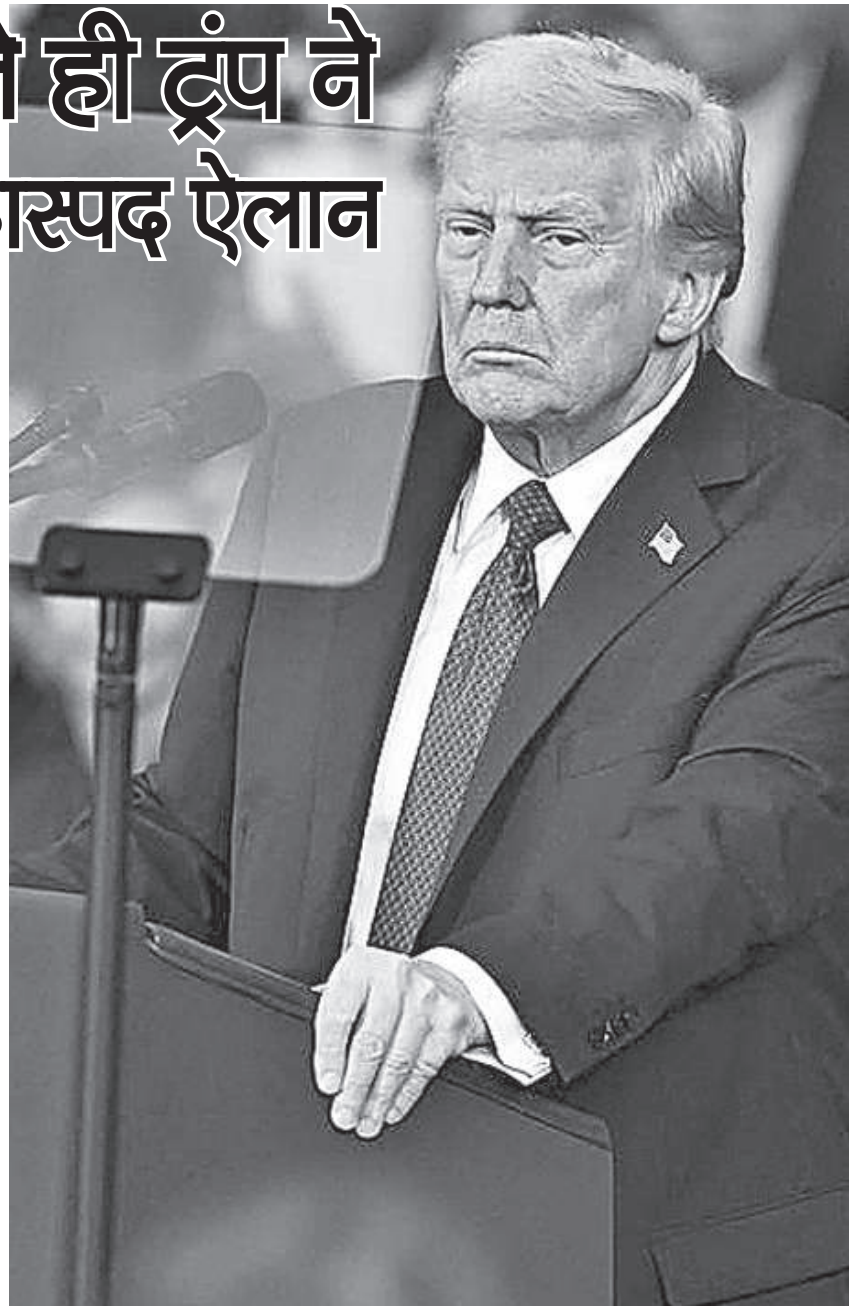

47 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने कई ऐलान किए. उन्होंने कहा कि अमेरिका को महान बनाने के लिए ही "भगवान" ने उनकी जान बचाई. अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिए अपने पहले भाषण में डॉनल्ड ट्रंप ने कई बड़े ऐलान किए. अपने पहले दिन शुल्क लागू करने से परहेज करते हुए यह दांव खेला है कि उनके कार्यकारी आदेश ऊर्जा की कीमतों को कम कर सकते हैं और महंगाई पर काबू पा सकते हैं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उनके कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उस दिशा में कैसे ले जा पाएंगे.

शपथ लेने के बाद ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती की नीतियों को पलटने और "कॉमनसेंस की क्रांति" लाने का वादा किया. ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, "हमारी संप्रभुता को दोबारा हासिल किया जाएगा. हमारी सुरक्षा को बहाल किया जाएगा. न्याय का तराजू फिर से संतुलित किया जाएगा."

उन्होंने यह भी वादा किया, "एक भयानक विश्वासघात को पूरी तरह से पलटने का मुझे जनादेश मिला है. मैं लोगों को उनका विश्वास, संपत्ति, लोकतंत्र और स्वतंत्रता वापस दूंगा." उन्होंने शपथ दिवस को अमेरिका का 'मुक्ति दिवस' करार दिया.

ट्रंप का शपथ ग्रहण उनके राजनीतिक करियर की ऐतिहासिक वापसी को दिखाता है. चार साल पहले, उन्हें कोविड-19 महामारी और आर्थिक संकट के बीच व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा था. हालांकि, दो महाभियोगों, आपराधिक आरोप और हत्या के प्रयासों के बावजूद, ट्रंप ने रिपब्लिकन मतदाताओं को संगठित कर फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया. उन्होंने कहा, "आज से अमेरिका का पतन खत्म हो गया है." एरिजोना की 63 वर्षीय सिंडे बेस्ट जैसे ट्रंप समर्थक, बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने कहा, "मैं नए अमेरिका के लिए तैयार हूं." शपथ ग्रहण के दिन की शुरुआत सेंट जॉन एपिस्कोपल चर्च में प्रार्थना सभा से हुई. इसके बाद ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पारंपरिक चाय और कॉफी के लिए मुलाकात की. यह नजारा उनके अतीत के तीखे और कड़वाहट भरे मुकाबले से बिल्कुल उलट था. जब ट्रंप अपनी कार से उतरे, तो बाइडेन ने कहा, "घर पर आपका स्वागत है."

पहले उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को सुप्रीम कोर्ट के जज ब्रेट कवनॉ ने शपथ दिलाई. उसके बाद ट्रंप ने अब्राहम लिंकन की ऐतिहासिक बाइबिल और अपनी पारिवारिक बाइबिल पर शपथ ली. समारोह के दौरान इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस और अन्य प्रमुख उद्योगपति भी मौजूद थे.

---पहले ही दिन बड़े फैसले

ट्रंप ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कई बड़े कदम उठाने की योजना बनाई है. इनमें सीमा पार नियंत्रण सख्त करना, जीवाश्म ईंधन का उत्पादन बढ़ाना और संघीय एजेंसियों में विविधता, समानता और समावेश के कार्यक्रमों को समाप्त करना शामिल है.

उन्होंने कहा, "आज से अमेरिका की पूर्ण बहाली शुरू होती है." हालांकि, आलोचकों ने इन कदमों को नागरिक अधिकारों और पर्यावरण नीतियों के लिए खतरा बताया है.

ट्रंप का लौटना अमेरिका में विभाजन को और बढ़ा सकता है. उनके आलोचकों ने उनके आपराधिक रिकॉर्ड और 6 जनवरी, 2021 के कैपिटॉल दंगों में उनकी भूमिका पर सवाल उठाया है. ट्रंप ने वादा किया है कि वह दंगे में शामिल कई व्यक्तियों को माफ कर देंगे.

मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम उनके सपने को साकार करने के लिए एक साथ प्रयास करेंगे."

ट्रंप का प्रशासन तुरंत आप्रवासन, आर्थिक नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा. इसमें दक्षिणी सीमा पर आपातकाल घोषित करना, ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रयास, और अंतरिक्ष में अमेरिकी उपस्थिति बढ़ाना शामिल है. ट्रंप के समर्थक इलॉन मस्क ने भाषण के दौरान कई बार तालियां बजाई.

ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, "महंगाई का संकट भारी खर्चों के कारण हुआ." उन्होंने सुझाव दिया कि तेल उत्पादन बढ़ाने से कीमतें कम हो सकती हैं.

इस भाषण में ट्रंप ने जो आदेश तुरंत जारी करने की बात कही, उनमें तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन से जुड़े नियम-कानूनों को कम करके

उत्पादन बढ़ाने और राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करने की बात शामिल है, जिससे कि चीन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों में प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक बिजली उत्पादन शुरू किया जा सके. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप एक राष्ट्रपति आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें महंगाई को कम करने के लिए एक व्यापक सरकारी दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है. अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर यह जानकारी दी.

ट्रंप ने अपने अभियान और चुनाव जीतने के बाद चीन, मेक्सिको, कनाडा और दूसरे देशों पर शुल्क लगाने की धमकी दी थी, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया. ट्रंप ने कहा कि इलेक्ट्रिक कार "आदेश" समाप्त किया जाएगा. हालांकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की नीतियां बनाई थीं, ना कि कोई आदेश जारी किया था.

व्हाइट हाउस अधिकारी ने कहा कि ट्रंप फिलहाल टैरिफों पर रोक लगा रहे हैं और एजेंसियों को व्यापार मामलों का अध्ययन करने का निर्देश देंगे. कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने कहा, "शायद उन्होंने शुल्क की धमकी को फिलहाल रोक दिया है. हमें किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा."

---ट्रंप की योजनाएं

महंगाई पर काबू पाने के ट्रंप के वादे में कई चुनौतियां हैं. बाइडेन प्रशासन के दौरान महंगाई दर दो सालों में कम हुई, लेकिन कीमतें अभी भी वेतन वृद्धि से अधिक रहीं. इसकी वजह, मकानों की कमी, तेल उत्पादन का रिकॉर्ड गिरता स्तर और 2022-23 में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें 11 बार बढ़ाना माना जा रहा है.

ऊर्जा की कीमतें महंगाई पर बड़ा प्रभाव डालती हैं. ट्रंप ने अमेरिका की "ऊर्जा प्रभुत्व" बहाल करने का वादा किया है. हालांकि, ऊर्जा का उपभोक्ता खर्च में औसत योगदान सिर्फ 6 फीसदी है.

2017 के टैक्स घटाने की सीमा को बढ़ाना और विस्तार करना शामिल है, जिसकी लागत अगले 10 वर्षों में 40 खरब डॉलर से अधिक हो सकती है. उन्होंने बाइडेन प्रशासन की नवीकरणीय ऊर्जा सब्सिडी को समाप्त करने, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 7,500 डॉलर के टैक्स क्रेडिट को हटाने, वाहनों के लिए ग्रीन हाउस गैस और अन्य प्रदूषण पर नियमों को नरम करने जैसी योजनाओं का जिक्र किया.

---कई विवादास्पद एलान

अपने भाषण में ट्रंप ने कई ऐसे बयान दिए जिन पर अलग-अलग हल्कों में आपत्ति हो सकती है. उन्होंने कहा कि अब अमेरिका सिर्फ दो लिंगों को मान्यता देगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. इस ऐलान से ट्रांसजेंडर समुदाय को धक्का पहुंच सकता है.

उन्होंने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से हटाने की घोषणा की है. यह फैसला दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक को जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों से बाहर कर देता है. पेरिस समझौता, 2015 में किया गया एक वैश्विक समझौता है, जिसमें सरकारें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए सहमत हुई थीं.

साथ ही, ट्रंप ने एलान किया कि अमेरिका पनामा नहर को वापस ले लेगा. उन्होंने कहा, "हमने इसे पनामा को दिया था, और अब हम इसे वापस ले रहे हैं." पनामा पहले ही इस बात का विरोध कर चुका है. ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर को चीन संचालित कर रहा है और अमेरिका के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है.

---अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं

ट्रंप के शपथ ग्रहण पर दुनियाभर के नेताओं ने बधाई और प्रतिक्रियाएं दी हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सबसे पहले बधाई देने वाले नेताओं में से थे. सोशल मीडिया साइट एक्स पर मोदी ने लिखा, "मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डॉनल्ड जे. ट्रंप, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आपके ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर हार्दिक बधाई! मैं एक बार फिर हमारे दोनों देशों के लाभ और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए आपके साथ करीब से काम करने का इंतजार कर रहा हूं. आपके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं."

जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने कहा, "आज राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण किया. बधाई हो! अमेरिका हमारा सबसे करीबी सहयोगी है, और हमारी नीति का लक्ष्य हमेशा एक अच्छे ट्रांसअटलांटिक संबंध को बनाए रखना है. 27 सदस्य देशों और 40 करोड़ से अधिक लोगों के साथ, यूरोपीय संघ एक मजबूत संघ है."

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने कहा, "सदियों से, हमारे देशों के बीच का संबंध सहयोग, सहभागिता और स्थायी साझेदारी का रहा है. हमने मिलकर दुनिया को तानाशाही से बचाया है और अपनी साझा सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम किया है. राष्ट्रपति ट्रंप के ब्रिटेन के प्रति लंबे समय से चले आ रहे स्नेह और ऐतिहासिक संबंधों के साथ, मुझे विश्वास है कि इस मित्रता की गहराई बनी रहेगी."

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेयर लाएन ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आपके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं. यूरोपीय संघ आपके साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रतीक्षा करता है. साथ मिलकर, हमारे समाज बड़ी समृद्धि हासिल कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं. यही ट्रांसअटलांटिक साझेदारी की स्थायी ताकत है."

कोयला रॉयल्टी मद में बकाया, फैसला कमेटी के निर्णय के बाद : जी. किशन

सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी की आलाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक हुई थी। बैठक के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री ने इस मामले के समाधान की दिशा में पहल करने का भरोसा दिलाया

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कोयला रॉयल्टी मद में झारखंड सरकार द्वारा मांगे जा रहे 1.36 लाख करोड़ बकाए पर कहा है कि कमेटी बनी है। कमेटी के निर्णय के बाद पैसे दिए जाएंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री ने राजधानी रांची में कहा कि इन बातों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातें हुई हैं। केंद्र सरकार किसी का पैसा नहीं रोकती। हम लोग जनता का विकास चाहते हैं।

सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी की आलाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक हुई थी। बैठक के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री ने इस मामले के समाधान की दिशा में पहल करने का भरोसा दिलाया था। मालूम हो कि पिछले माह लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा कोयला रॉयल्टी मद में झारखंड के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग और दावे को केंद्र सरकार द्वारा खारिज करने की बात कही गई थी। तब काफी विवाद हुआ था। उसके बाद यह बैठक हुई थी। राज्य सरकार ने बैठक में खनिज रॉयल्टी को लेकर क्षेत्रवार बकाया राशि का आकलन केंद्रीय कोयला मंत्री के सामने रखा था। इस पर केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा था कि केंद्र सरकार के अधिकारी राज्य सरकार के साथ मिलकर इसकी प्रमाणिकता का आकलन करें। केंद्रीय कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री को बकाया के भुगतान का भरोसा दिलाया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों तथा कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया और इसकी अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों बीच कोयला खनन से जुड़े विभिन्न विषयों/ मुद्दों तथा उसके समाधान को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला एक ऐसा विषय है,

जिसके तहत इसके खनन, उत्पादन, परिवहन, जमीन अधिग्रहण मुआवजा, विस्थापन के साथ डीएमएफटी फंड एवं सीएसआर एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे कोल माइनिंग से संबंधित समस्याओं का जहां समाधान निकलेगा वहीं लोगों के बीच माइनिंग को लेकर जो नकारात्मक मानसिकता बनती है उसे बदलने में भी सहूलियत होगी । इससे लोगों की उम्मीदें भी जागेगी और कोल परियोजनाओं को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उसको काफी हद तक रोका जा सकता है ।

---बकाया भुगतान की मांग रखी

बैठक में खनिज रॉयल्टी को लेकर राज्य सरकार ने विषयवार/ क्षेत्रवार अलग-अलग परियोजनावार बकाया राशि का आकलन, जो जिला स्तर पर खनन कंपनियां के साथ तैयार किया गया है, केंद्रीय कोयला मंत्री के समक्ष उसे रखा गया तथा उस बकाये तथा गणना का आधार उपलब्ध कराया गया। जिस पर केंद्रीय कोयला मंत्री ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार के अधिकारी राज्य सरकार के साथ मिलकर इसकी प्रमाणिकता का आकलन करें। केंद्रीय कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री को बकाया के भुगतान का भरोसा दिलाया।

विस्थापित रैयतों को स्टेक होल्डर बनाने पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल खनन परियोजनाओं को लेकर जमीन का जो अधिग्रहण होता है। जो रैयत विस्थापित होते हैं, उन्हें सिर्फ मुआवजा और नौकरी देने की व्यवस्था से हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। विस्थापित रैयतों को को खनन परियोजनाओं में स्टेक होल्डर बनाकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इससे उनका हम विश्वास भी जीतेंगे और सीएसआर से जुड़ी गतिविधियों तथा डीएमएफटी फंड का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने खनन परियोजनाओं में कार्य को लेकर जो टेंडर जारी किए जाते हैं। उसमें छोटे-मोटे कार्यों का टेंडर विस्थापितों को मिलना चाहिए। इस दिशा में कोल मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में जमीन से लोगों का भावनात्मक लगाव होता है। ऐसे में जब खनन परियोजनाओं को लेकर जमीन अधिग्रहण होता है तो लोगों को काफी तकलीफें होती है। वे अपनी जमीन से अलग होना नहीं चाहते हैं। विस्थापितों को सिर्फ मुआवजा तथा नौकरी देकर सारी खुशियां नहीं दे सकते हैं । ऐसे में जमीन अधिग्रहण से जो रैयत विस्थापित होते हैं उनकी कोल खनन परियोजनाओं में इस तरह भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि वे अपना पूरा सहयोग सरकार और कोयला कंपनियों को दे सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऐसी कई कोल परियोजनाएं हैं, जहां खनन का कार्य पूरा हो चुका है और कोल कंपनियों के द्वारा उस जमीन को यूं ही छोड़ दिया गया है । वह जमीन ना तो राज्य सरकार को हस्तांतरित की जा रही है और ना ही उसका कोई सदुपयोग हो रहा है। इस वजह से बंद हो चुकी कोल खनन परियोजनाओं में अवैध माइनिंग हो रही है, जिस वजह से कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। ऐसे में पड़े खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस किया जाय।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कोल कंपनियों के द्वारा कोयला खनन क्षेत्र में चल रहे सीएसआर एक्टिविटीज और डीएमएफटी फंड के इस्तेमाल की जानकारी ली। कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में कोल कंपनियों के द्वारा कोल खनन क्षेत्र के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव या इलाके में सीएसआर एक्टिविटी संचालित की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएसआर एक्टिविटीज का दायरा और बढ़ना चाहिए । कोयला खनन परियोजनाओं के कम से कम 50 किलोमीटर के रेडियस में सीएसआर एक्टिविटीज के तहत क्षेत्र के विकास से जुड़ी योजनाओं को लागू किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिजों का जिस तरह से खनन हो रहा है उससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इस दिशा में गंभीरता से सोच कर कदम उठाने की जरूरत है । उन्होंने कहा कि झरिया में जमीन के नीचे वर्षों से आग लगी हुई है लेकिन उस पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है । वही घाटशिला- में जादूगोड़ा में यूरेनियम के खनन की वजह से लोगों के समक्ष स्वास्थ्य से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं आ रही है। इसका निदान होना चाहिए। कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि कोयला खदानों के नीचे लगी आग को बुझाने और खनन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मामले में केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठाएगी

मुख्यमंत्री ने दिए सुझाव

कोल कंपनियां यहां स्थायी प्रशिक्षण केंद्र खोलने की पहल करे। इन प्रशिक्षण केंद्र में विस्थापित परिवारों के युवाओं को वैसे मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाए जिसका इस्तेमाल कोयला खनन में किया जाता है। इससे कोल परियोजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और बाहर से श्रमिकों को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कोल कंपनियां माइनिंग कार्यों में भी महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए।

जो कोल ब्लॉक निजी कंपनियों को आवंटित किए गए हैं , उनमें स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था होनी चाहिए। झारखंड में मीनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में भी कोयला मंत्रालय इनिशिएटिव ले। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कोल इंडिया का मुख्यालय झारखंड में लाने का एक बार फिर आग्रह किया।

उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, केंद्रीय कोयला सचिव विक्रम देव, एडिशनल सेक्रेटरी विस्मिता तेज, राज्य सरकार में सचिव अबू बकर सिद्दीक, प्रशांत कुमार, चंद्रशेखर, जितेंद्र सिंह, उमाशंकर सिंह, निदेशक खनन राहुल कुमार सिन्हा, प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा, कोल इंडिया के अध्यक्ष पीएम प्रसाद, सीसीएल के सीएमडी निलेन्दु कुमार सिंह, बीसीसीएल के सीएमडी एस दत्ता, ईसीएल के सीएमडी सतीश झा, सीएमपीडीआई के सीएमडी मनोज कुमार हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सीएमडी घनश्याम शर्मा समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।

केंद्रीय कोयला मंत्री ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी

केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कांके, रांची स्थित रिनपास के समीप 200 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। यह अस्पताल कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं से युक्त होगा।

कोयला मंत्री ने हॉस्पिटल की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसे क्षेत्र के नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर मंत्री श्री रेड्डी ने कहा यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोयला क्षेत्र के विकास और क्षेत्रीय सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के पूर्ण हो जाने पर इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करने का प्रयास करेंगे ।

इस अवसर पर रांची के सांसद एवं रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा, पूर्व सांसद सुनील सिंह ,कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त अतिरिक्त सचिव कोयला श्रीमती विस्मिता तेज, कोयला मंत्री के निजी सचिव बक्की कार्तिकेयन, अतिरिक्त निजी सचिव ए. वेंकटेश्वर रेड्डी, कोल इंडिया के चेयरमैन पी.एम. प्रसाद, सीसीएल के सीएमडी निलेंदु कुमार सिंह, सीएमपीडीआईएल के सीएमडी मनोज कुमार, सीसीएल के निदेशक (वित्त) पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्मिक) हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक (तकनीकी/संचालन) हरीश दूहन, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) पंकज कुमार और श्रमिक संघ के प्रतिनिधि गण उपस्थित थे।

आईआईसीएम का परिभ्रमण : कोयला एवं खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने भारतीय कोयला खान संस्थान (आईआईसीएम) का दौरा किया, जहां उन्होंने युवा प्रबंधन प्रशिक्षुओं और "ज्योति कार्यक्रम" के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रही सभी महिला प्रतिभागियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "देश के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके योगदान को मान्यता देना आवश्यक है।"

उन्होंने युवा पेशेवरों को यह संदेश दिया कि वे अपने कार्य को केवल एक रोजगार के रूप में न देखें, बल्कि इसे देश सेवा के एक अवसर के रूप में अपनाएं। उन्होंने युवाओं को अपने कार्यक्षेत्र में नई सोच और नवाचार को शामिल करने का भी आह्वान किया। मंत्री श्री रेड्डी ने इस अवसर पर पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया ।

कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त ने महिलाओं की भूमिका कोयला उद्योग में सशक्त बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाना और उनके साथ तालमेल बिठाना समय की मांग है।

अतिरिक्त सचिव कोयला, श्रीमती विस्मिता तेज ने महिला प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए उनके योगदान को कोयला क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया।

कोल इंडिया के चेयरमैन पी.एम. प्रसाद ने भी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय कोयला खान संस्थान की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा संस्थान कोयला क्षेत्र के युवाओं को उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करने और उन्हें नेतृत्व के लिए तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।"

सुरक्षा बैरक का उद्घाटन व बहुमंजिला आवासीय भवन का हुआ शिलान्यास

कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने रांची के गांधीनगर आवासीय परिसर में सीसीएल के लिए दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन और सीसीएल कर्मियों के लिए बहुमंजिला आवासीय भवनों का शिलान्यास शामिल है।

मंत्री ने गांधीनगर में सीसीएल के सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना की लागत 2.33 करोड़ है और इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह केंद्र सुरक्षा कर्मियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसमें 40 बिस्तरों वाला डॉर्मिटरी, कक्षाएं, जिम, डाइनिंग हॉल और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। इस केंद्र के माध्यम से सीसीएल के 1600 से अधिक सुरक्षाकर्मियों और भविष्य में शामिल होने वाले नए कर्मियों को आधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। यह परियोजना न केवल सुरक्षा कर्मियों की दक्षता को बढ़ाएगी, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और अनुशासन में भी सुधार करेगी। इसके अतिरिक्त मंत्री ने गांधीनगर में सीसीएल कर्मियों के लिए चार बहुमंजिला आवासीय भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया। इस परियोजना में ग्राउंड+8 मंजिल के चार टावर बनाए जाएंगे, जिनमें कुल 112 आवासीय इकाइयां होंगी। इन इकाइयों में बी-टाइप के 32, सी-टाइप के 64 और डी-टाइप के 32 फ्लैट शामिल होंगे। परियोजना की कुल लागत 77.63 करोड़ है। इन भवनों में ग्रीन बिल्डिंग के तहत अत्याधुनिक सुविधाएं, जैसे कम्युनिटी पार्क, बैडमिंटन कोर्ट और वॉकिंग एरिया उपलब्ध कराए जाएंगे। इस परियोजना का निर्माण कार्य 4 जनवरी 2025 को शुरू होकर 4 जनवरी 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके उपरांत उन्होंने सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल और सीएमपीडीआईएल की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोयला उत्पादन, कर्मचारियों के कल्याण और कंपनी की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में कोल इंडिया के अध्यक्ष पी एम प्रसाद सहित सभी कंपनियों के सीएमडी एवं उच्च अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री ने इन कंपनियों की प्रगति का आकलन किया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

कोयला मंत्री ने बीसीसीएल में अनुकंपा नियोजन पत्रों का किया गया वितरण

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के हाथों से बीसीसीएल में अनुकंपा आधार पर नियोजन पाने वाले पांच लाभार्थियों को नियोजन पत्र सौंपा गया।

बीसीसीएल द्वारा जनवरी 2025 माह में 100 नियोजन दिये जाने हैं, इस क्रम में पाँच पात्र लाभार्थियों को मंत्री जी. किशन रेड्डी हाथों नियोजन देकर इसकी शुरुआत हूई। मौके पर कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त, अतिरिक्त सचिव श्रीमती विश्मिता तेज, कोल इंडिया के चेयरमैन पी एम प्रसाद भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता ने बताया कि कंपनी ने इस वर्ष अब तक 442 लाभार्थियों को नियोजन दिया गया है। दिसंबर माह में नियोजन शिविर 2.0 में 117 लाभार्थियों को नियोजन पत्र सौंपे गये।

वर्ष 2025 के प्रथम माह में ही 100 लोगों को नियोजन दिया जा रहा है। इसमें पांच लोगों को आज कोयला मंत्री के हाथों नियोजन पत्र सौंपे गये हैं। बाकी के 95 लाभार्थियों को आगामी सप्ताह में नियोजन पत्र वितरित किये जाएंगे।

इसके अलावा बीसीसीएल ने हाल ही में एससी/एसटी और ओबीसी के लिए विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से 77 जूनियर ओवरमैन के पदों पर भी

भर्ती की है।साथ ही चिकित्सकों और नर्सों के पदों को भी भरा गया है। वर्ष 2024-25 के अंत तक बीसीसीएल द्वारा 600 से अधिक लोगों को नियोजन दे दिया जएगा।

PRANAB NAMAN MINERALS PRIVATE LIMITED

Happy

REPUBLIC DAY

Being born in a great nation like India
is a matter of pride and dignity for us.

PNM

6517966093

WWW.PNMPL.COM

CCL
Fuelling Sustainable Growth

5 DECADES OF UNEARTHING ENERGY

26 जनवरी, 2025

76वें गणतंत्र दिवस

की हार्दिक

शुभकामनाएँ

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कम्पनी)
दरभंगा हाउस, राँची – 834001 (झारखण्ड)

adani

गणतंत्र के सिद्धांतों का
सम्मान है देश की शान

देश के 76वें गणतंत्र दिवस पर, हम अपने लोकतंत्र की आधारशिला – भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। हमारी एकता और अखंडता का ये चिन्ह, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को उनका अधिकार प्रदान करता है। आइए हम सब मिलकर, इसके महान मूल्यों को अपनाएं और एक बेहतर कल का निर्माण करें।

अदाणी परिवार की ओर से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

मेधा
ताज़गी झारखण्ड की
Shakti
बेजोड़ स्वाद
और
मलाईदार दूध
मेधा
Fortified with
Vitamin A & D
Shakti
Pasteurized Standardized Milk
Fortified with Vitamin A & D
झारखण्ड का अपना दूध
मेधा
Fortified with
Vitamin A & D
Shakti
Pasteurized Standardized Milk
Fortified with Vitamin A & D
झारखण्ड के ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों से
शहरी उपभोक्ताओं तक
www.fb.com/medhacoop
jmf.coop
7544003456
jmf_coop
MEDHA DAIRY

TOTAL MINING SOLUTIONS

One stop solution

India's one of the largest consultancy organization with over 47 years of experience as in-house consultant to Coal India Limited is diversifying its activities to other mine owners.

An ISO 9001:2015 & 37001:2016 Certified Mini-Ratna Company with Headquarters at Ranchi and 7 strategically located Regional Institutes to provide door-step services.

Recipient of the SCOPE Meritorious Award from President of India for R&D initiatives in the Coal Sector.

Facilitated production augmentation of CIL from 79 Mt in 1975-76 to 773.64 Mt in 2023-24.

Offers full range of services in the sphere of resource exploration, mining, beneficiation and development of mine from concept to commissioning including environmental, geomatics and specialized services including Blasting, NDT, CBM/CMM & Coal Gasification, etc.

Expertise under one roof

- *Integrated Exploration services*
- *Preparation of Master Plans of Coalfields*
- *Project Planning & Design including concept to commissioning to closure for coal & minerals.*
- *Engineering Services including Planning for Infrastructure Development*
- *Coal Beneficiation*
- *Preparation of EIA/EMP.*
- *Environment Monitoring and Mine Closure Planning*
- *Remote sensing surveillance and monitoring*
- *Drone/UAV based survey and mapping services*
- *Hydrogeological services*
- *Project Management Consultancy services for Civil construction supervision, Solar Power Projects, etc.*
- *Lab services viz. Coal characterization, Washability of Coal, Mine Air, Water & Soil quality, Physico-Mechanical properties of rocks, CBM related studies, etc.*
- *Specialized Services in the field of Blasting, Ventilation, Support Design, NDT, Clean Coal Technology like CBM, CMM & Coal Gasification, etc.*

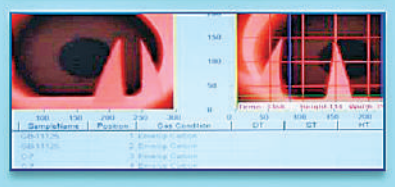

CENTRAL MINE PLANNING AND DESIGN INSTITUTE LIMITED
(A Subsidiary of Coal India Limited)
Gondwana Place, Kanke Road,
Ranchi 834 031 (Jharkhand) INDIA

Tel: +91 651 2230116/2230483
Fax: +91 651 2232249/2231447
Email: gmbd.cmpdi@coalindia.in

www.cmpdi.co.in /CMPDIL/ /cmpdil/ /cmpdi /CMPDIL/

अनुमानों पर आधारित है श्रद्धालुओं की संख्या

प्रयागराज महाकुंभ

प्रयागराज में महाकुंभ मेले के पहले स्नान पर्व मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के संगम पर स्नान करने का दावा है। मुख्य पर्व 29 जनवरी को है, उस दिन इससे कई गुना ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।

14 जनवरी को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का पहला शाही स्नान (अमृत स्नान) था और प्रशासन का दावा है कि इस दिन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने एक्स हैंडल पर ये जानकारी दी। देर शाम उन्होंने एक्स पर लिखा, "प्रथम अमृत स्नान पर्व पर आज 3.50 करोड़ से अधिक पूज्य संतों/ श्रद्धालुओं ने अविरल-निर्मल त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया।"

45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान : मकर संक्रांति से एक दिन पहले पौष पूर्णिमा पर भी करीब डेढ़ करोड़ लोगों ने स्नान किया था। यानी सिर्फ दो दिनों में पांच करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान का दावा प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। प्रयागराज में कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान तीन प्रमुख शाही स्नान होंगे। अगला शाही स्नान (अमृत स्नान) 29 जनवरी को अमावस्या को होगा और फिर 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर होगा। इसके अलावा माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी कुंभ स्नान किया जाएगा।

सबसे ज्यादा भीड़ अमावस्या पर होती है और अनुमान है कि उस दिन स्नान करने वालों का आंकड़ा दस करोड़ के आस-पास होगा। माना जा रहा है कि इस बार के महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे।

हालांकि श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या को लेकर कई तरह के सवाल भी उठते हैं लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इस धार्मिक आयोजन में स्नान करने वालों यानी भीड़ के आंकड़े जुटाए कैसे जाते हैं? प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है

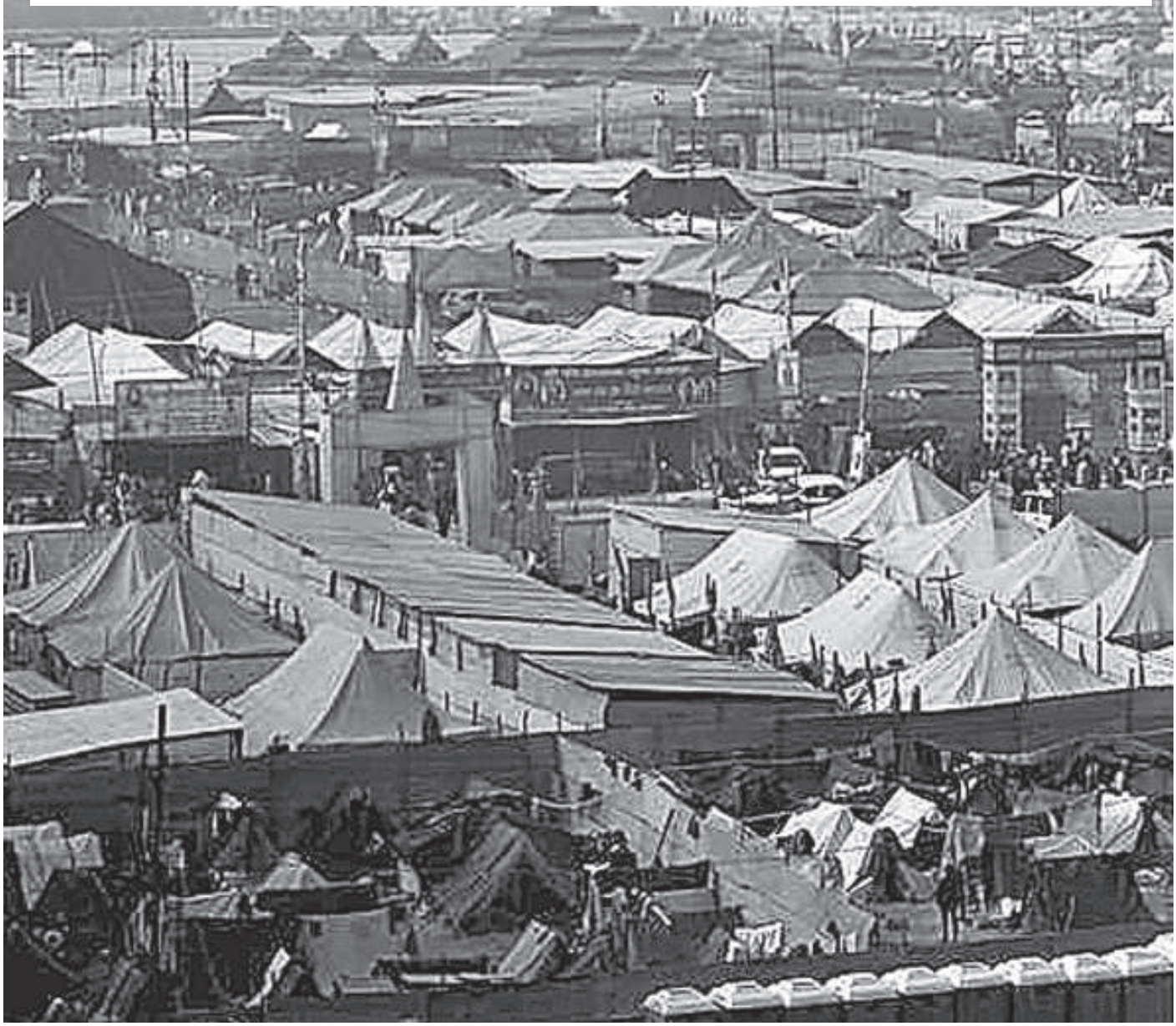

लेकिन भीड़ के आंकड़े पहले भी आया करते थे और स्नान पर्वों पर भीड़ के तमाम रिकॉर्ड बनते और टूटते थे। आंकड़ों पर सवाल भी हमेशा उठते रहे हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग

प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के मुताबिक, इस बार कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं की गिनती के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया, "महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सटीक गिनती के लिए इस बार एआई से लैस कैमरे लगाए गए हैं। यह पहली बार है जब एआई के जरिए श्रद्धालुओं की सटीक संख्या जानने की कोशिश की जा रही है।

इसके अलावा श्रद्धालुओं को ट्रैक करने के लिए कुछ और भी इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में दो सौ जगहें ऐसी हैं जहां पर बड़ी संख्या में अस्थाई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज शहर के अंदर भी 268 जगहों पर 1107 अस्थाई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा सौ से ज्यादा पार्किंग स्थलों पर भी सात सौ से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिनसे बाहर से आने वाले यात्रियों का अनुमान लगाया जाता है।"

श्रद्धालुओं की गिनती के लिए एआई लैस कैमरे हर मिनट में डेटा अपडेट करते हैं। ये सिस्टम सुबह तीन बजे से शाम 7 बजे तक पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। चूंकि मुख्य पर्वों पर स्नान काफी सुबह ही शुरू हो जाता है इसलिए इन्हें उससे पहले ही एक्टिव कर दिया जाता है।

मंडलायुक्त के मुताबिक, एआई का उपयोग करते हुए क्राउड डेंसिटी एल्गोरिदम से लोगों की गिनती का भी प्रयास किया जा रहा है। एआई आधारित क्राउड मैनेजमेंट रियल टाइम अलर्ट जेनरेट करेगा, जिसके जरिए संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की गिनती करना और उनकी ट्रैकिंग करना आसान होगा।

इसके अलावा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती नावों और ट्रेनों, बसों और निजी वाहनों से आने वाले लोगों की संख्या से भी की जाती है। इसके अलावा मेले में साधु-संतों और उनके कैंप में आने वाले लोगों की संख्या को भी भी श्रद्धालुओं की कुल संख्या में जोड़ा जाता है और मेले से जुड़ी सड़कों पर गुजरने वाली भीड़ को भी ध्यान में रखा जाता है।

हालांकि वास्तविक संख्या बता पाना अभी भी बहुत मुश्किल है क्योंकि तमाम यात्री अलग-अलग जगहों पर जाते हैं और यहां तक कि अलग-अलग घाटों पर भी जाते हैं। ऐसे में उनकी गिनती एक बार से ज्यादा ना हो, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग के अध्यक्ष रह चुके प्रोफेसर हेरम्ब चतुर्वेदी ने कुंभ की ऐतिहासिकता पर चर्चित पुस्तक 'कुंभः ऐतिहासिक वांगमय' लिखी है। प्रोफेसर चतुर्वेदी साल 2013 के कुंभ मेले में कुंभ मेला कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं।

वो कहते हैं, "2013 से पहले श्रद्धालुओं की गिनती के लिए मेला के डीएम और एसएसपी की रिपोर्ट को ही सच माना जाता था और उनकी रिपोर्ट इसी आधार पर तैयार होती थी कि कितनी बसें आईं, कितनी ट्रेनें आईं और उनसे कितने लोग उतरे। निजी वाहनों पर भी नजर रखी जाती थी। इसके अलावा अखाड़ों से भी उनके यहां आने वाले श्रद्धालुओं की जानकारी ली जाती थी।"

चतुर्वेदी का यह भी कहना है, "पहले बिल्कुल संगम के किनारे तक जाने देते थे, तब यह जानना बहुत आसान था कि कितने लोग निकले होंगे। लेकिन अब तो ज्यादातर लोगों को शहर के भीतर ही रोक दिया जाता है। 2013 में आईआईटी की मदद से जब डिजिटाइजेशन शुरू हुआ तब से कुछ वास्तविक आंकड़े आने लगे। हालांकि डिजिटाइजेशन के दौर में फजिंग भी बहुत होती है।"

सांख्यिकीय तरीका

साल 2013 के कुंभ में पहली बार सांख्यिकीय विधि से भीड़ का अनुमान लगाया गया था। इस विधि के अनुसार, एक व्यक्ति को स्नान करने के लिए करीब 0।25 मीटर की जगह चाहिए और उसे नहाने में करीब 15 मिनट का समय लगेगा। इस गणना के मुताबिक एक घंटे में एक घाट पर अधिकतम साढ़े बारह हजार लोग स्नान कर सकते हैं। इस बार कुल 44 घाट बनाए गए हैं जिनमें 35 घाट पुराने हैं और नौ नए हैं। यदि सभी 44 घाटों पर लगातार

18 घंटे स्नान कर रहे लोगों की संख्या जोड़ी जाए तो यह संख्या प्रशासन के दावे से काफी कम बैठती है, मुश्किल से एक तिहाई।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मीडिया स्टडीज विभाग में सीनियर फैकल्टी एसके यादव वरिष्ठ फोटोग्राफर हैं और साल 1989 से लगातार हर कुंभ और अर्ध कुंभ को कवर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भीड़ को नापने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, आज भी सिर्फ अनुमान ही लगाया जा रहा है भले ही हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हों।

एसके यादव बताते हैं, "मकर संक्रांति के दिन मैं तो उसी जगह यानी संगम नोज पर ही था। सड़कें इस बार काफी चौड़ी की गई हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मकर संक्रांति के मौके पर साल 2013 और 2019 के कुंभ में जितनी भीड़ थी, इस बार उतनी नहीं थी।"

महाप्रसाद रसोई में अदाणी परिवार की सास-बहू का दिखा अद्भुत रूप

महाकुंभ के भव्य आयोजन में जब श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा रहे थे, तब सेक्टर 19 स्थित इस्कॉन पंडाल में 21 जनवरी 2024 को एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। इस्कॉन के विशाल रसोईघर में हाथों से मटर की फलियां छीलती डॉ. प्रीति अदाणी अपनी बहू और नन्ही पोती के साथ बैठी थीं।

सबका मनमोह गई सास-बहू की जोड़ी

इस्कॉन रसोई में सेवा करने वाली महिलाओं की टोली जुटी हुई थी—कोई सब्जी छील रहा था तो कोई हल्के हंसी-मजाक के बीच सेवा में जुटा हुआ था। इस बीच डॉ. प्रीति अदाणी ओर उनकी बहू परिधि अदाणी उनके बीच पहुंचती हैं और मुस्काते हुए साथ ही सेवा करना शुरू कर देती हैं।

मटर के दानों को अपने हाथों से अलग करते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनके साथ उनकी बहू परिधि अदाणी भी मटर छीलने का काम पूरी लगन से कर रही थीं। इस सबके बीच उनकी पोती भी गोद में बैठ कर मटर छीलने की कोशिश करती दिखी। अपनी मां, पत्नी और बेटी को पास ही खड़े गौतम अदाणी के बेटे करण अदाणी भी तल्लीनता से देख रहे थे।

रोटी बनाने के काम में दिखी दक्षता : इसके बाद डॉ. प्रीति अदाणी अपनी बहु के साथ उस जगह पर पहुंचीं जहां पर रोटी बनाने का काम चल रहा था। वहां पहुंचते ही सास-बहू की जोड़ी जमीन पर बैठ गई और रोटियों पर घी लगाने का काम करने लगी। रोटी मेकिंग मशीन से रोटी बन कर जैसे ही बाहर आती डॉ. प्रीति अदाणी और परिधि अदाणी फौरन उन रोटियों में घी लगा कर श्रद्धालों को परोसने के लिए आगे बढ़ा देते। सादगी, सेवा और संस्कृति—तीनों का यह सुंदर संगम कुंभनगरी में अपनी एक अलग पहचान छोड़ गया।

21 जनवरी 2025 को गौतम अदाणी सपरिवार महाकुंभ स्थल प्रयागराज आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने इस्कान में प्रसाद सेवा, पवित्र संगम में स्नान एवं पूजा-अर्चना और बड़े हनुमान जी के दर्शन किए। बता दें कि महाकुंभ के मौके पर अदाणी समूह ने इस्कॉन के साथ मिलकर प्रतिदिन 1 लाख लोगों में महाप्रसाद वितरण और गीता प्रेस के साथ मिलकर 1 करोड़ आरती संग्रह वितरण का संकल्प लिया है।

बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने नालको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने भुवनेश्वर में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के निगम कार्यालय में इसके अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का पदभार ग्रहण किया।

नालको में शामिल होने से पूर्व, श्री सिंह बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक और सेल के बोर्ड के सदस्य थे। खानों और इस्पात क्षेत्रों में 35 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, श्री सिंह की रणनीतिक दृष्टि और गहन उद्योग विशेषज्ञता सेल के आधुनिकीकरण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने, राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुरूप भारत के इस्पात क्षेत्र के विकास और स्थिरता को आगे बढ़ाने में सहायक रही है।

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, वर्ष 1989 में आईआईटी धनबाद (पूर्व में आईएसएम धनबाद) से माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और उनके पास मार्केटिंग में एमबीए की डिग्री भी है। वर्ष 1989 में भिलाई इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क खदान से इस्पात उद्योग में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले श्री सिंह ने तब से सेल के चार एकीकृत इस्पात संयंत्रों यानी बीएसपी (भिलाई इस्पात संयंत्र), बीएसएल (बोकारो स्टील लिमिटेड), डीएसपी (दुर्गापुर इस्पात संयंत्र) और आईएसपी (इस्को इस्पात संयंत्र) में अग्रणी नेतृत्व और परिचालन दोनों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उनकी व्यापक विशेषज्ञता खनन, ब्लास्ट फर्नेस, सिंटर प्लांट, रखरखाव और संयंत्र संचालन तक फैली हुई है।

श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति से नालको के विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों और नई परियोजनाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त होने की आशा है।

कोल इंडिया : निदेशक तकनीकी के पद पर अच्युत घटक की नियुक्ति को मिली मंजूरी

कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक तकनीकी पद के लिए अच्युत घटक की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी) अच्युत घटक को कोल इंडिया के निदेशक (तकनीकी) के पद नियुक्त करने के कोयला मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वे इस पद पर 31 मार्च, 2028 तक रहेंगे। यहां बताना होगा कि लोक उद्यम चयन बोर्ड ने 23 अगस्त, 2024 को इस पद के लिए श्री घटक के नाम की अनुशंसा की थी।

अच्युत घटक ने 1989 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर से माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री और 1992 में प्रथम श्रेणी माइनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। उन्होंने 1989 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से जूनियर एग्जिक्यूटिव ट्रेनी के रूप में करियर शुरू किया। श्री घटक ने अपनी आधिकारिक क्षमता में ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और अमेरिका का भी दौरा किया।

श्री घटक के पास कोयला उद्योग में 35 वर्षों का अनुभव है। वे 1 अक्टूबर, 2023 से सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

दिल्लीः किसका पलड़ा है भारी

दिल्ली विधानसभा चुनावों में पांच फरवरी को मतदान होगा। 'आप' का दिल्ली की राजनीति में एक दशक से दबदबा है लेकिन क्या पार्टी आज भी दिल्ली में उतनी ही लोकप्रिय है जितनी वह पहले थी?

दिल्ली में विधानसभा चुनावों के नजदीक आने की वजह से इन दिनों चुनावी राजनीति उबाल पर है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी कई मोर्चों पर 'आप' को घेरने की कोशिश कर रही है। आप भी पलटवार कर रही है और इन दोनों मुख्य खिलाड़ियों के बीच कांग्रेस भी अपना खोया हुआ दर्जा फिर से पाने की कोशिश कर रही है।

बीजेपी के लिए दिल्ली की लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मतदान के महीने भर पहले से ही आप के खिलाफ बीजेपी के कैंपेन की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है।

मोदी ने 'आप' को बताया 'आप-दा' : तीन जनवरी को उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी ने करोड़ों रुपयों की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और 'आप' पर खुल कर हमला किया।

'आप' को 'आप-दा' से जोड़ते हुए मोदी बोले, "10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आप-दा से घिरी हुई है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आप-दा में धकेल दिया।"

'आप' की दिल्ली सरकार पर कई तरह के घोटालों का आरोप लगाते हुए, प्रधानमंत्री ने 'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर लग रहे अपने सरकारी आवास पर करोड़ों खर्च करने के आरोपों का भी जिक्र किया। बीजेपी ने इस आवास को केजरीवाल के 'शीशमहल' का नाम दिया है।

शीश महल' बनाम 'राजमहल'

मोदी का यह भाषण बीजेपी के अन्य नेताओं के लिए एक तरह का संकेत साबित हुआ। उनके भाषण के बाद पार्टी के कई नेताओं ने केजरीवाल और आप पर 'शीशमहल' को लेकर निशाना साधा।

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि सीएजी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आप सरकार की देखरेख में मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन का खर्च दो सालों में आठ करोड़ से 33 करोड़ रुपए हो गया। यह रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है लेकिन इसके अंश मीडिया में लीक हो गए हैं।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इस खर्च में 96 लाख के पर्दे, 66 लाख का संगमरमर, 39 लाख के किचन उपकरण, 20 लाख के टीवी कॉन्सोल, 16 लाख के रेशमी कालीन, 4।80 लाख की मिनीबार आदि शामिल हैं। आप का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास पर हुए खर्च को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, जबकि मोदी की कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास पर 2,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आप ने 'शीश महल' के जवाब में प्रधानमंत्री आवास को बीजेपी का 'राजमहल' बताया है।

कथित 'शराब घोटाले' की आंच

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दम पर बनी आम आदमी पार्टी इस बार खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रही है। 2021 में आप सरकार दिल्ली में नई आबकारी नीति ले कर आई, जिसके तहत दिल्ली सरकार को शराब की बिक्री के व्यापार से पूरी तरह बाहर निकालने की योजना बनाई गई थी।

एक रिपोर्ट के अनुसार, इससे दिल्ली सरकार के राजस्व में 27 फीसदी की वृद्धि हुई और राज्य ने लगभग 8,900 करोड़ रुपये कमाए। लेकिन अप्रैल 2022 में जब दिल्ली में नए मुख्य सचिव नरेश कुमार की नियुक्ति हुई तो उन्होंने नई नीति में जांच के आदेश दिए।

जुलाई 2022 में मुख्य सचिव ने उप राज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने नीति में अनियमितताओं का दावा किया। इस रिपोर्ट में आरोप लगाए गए कि बतौर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब विक्रेताओं को लाइसेंस देने के बदले कमीशन और रिश्वत ली।

नरेश कुमार ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि लाइसेंस फीस और शराब की कीमतों में नियमों को ताक पर रखकर छूट दी गई, जिससे सरकार को करीब 144 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। यह भी दावा किया गया कि कमीशन और रिश्वत से मिली रकम का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने फरवरी 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनावों में किया।

बाद में उप राज्यपाल ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी और सीबीआई ने अगस्त 2022 में सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सिसोदिया के घर छापे मारे गए और कई बार पूछताछ के बाद 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

अक्टूबर 2023 में इसी मामले में पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी गिरफ्तार गए। आप सरकार में दिल्ली के गृह मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन को एक अन्य मामले में 2022 में ही गिरफ्तार किया जा चुका था।

आबकारी नीति मामले में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में अगस्त, 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और 21 मार्च, 2024 को इसी मामले में केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

2024 में धीरे धीरे केजरीवाल समेत इन सभी नेताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने बीजेपी और कांग्रेस को दिल्ली को 'भ्रष्टाचार से मुक्त' कराने का मुद्दा दे दिया।

राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि इन चुनावों में भ्रष्टाचार के इन आरोपों से पीछा छुड़ाना आप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा कहते हैं कि उनके अनुमान से इस बार आप को 45-50 सीटें मिल सकती हैं, जो पिछली बार की 67 सीटों के मुकाबले काफी कम हैं।

उन्होंने बताया, "आप पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग गए, उसके शीर्ष नेता जेल भी हो आए। आप की चादर मैली तो हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह मैली नहीं हुई है। इनके कई विधायकों के खिलाफ स्थानीय एंटी-इंकम्बेंसी ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने 20 विधायकों को दोबारा टिकट ना देने की जगह नए चेहरों को उतारा है, लेकिन लोग तो नाराज हो ही गए हैं।"

वहीं हार्ड न्यूज पत्रिका के संपादक संजय कपूर का मानना है कि आप पहले के मुकाबले कमजोर नजर तो आ रही है, लेकिन ज्यादा कमजोर नहीं। उन्होंने कहा, "बीजेपी पूरी ताकत के साथ आप को कमजोर करने की कोशिश कर रही है लेकिन आप ने हर बार दिखाया है कि उसमें काफी तीव्र पलटवार करने की भी क्षमता है और वो भी वहां जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा चोट लगे। जिस तरह बीजेपी के 'शीश महल' अभियान को आप ने 'शीशमहल' बनाम 'राजमहल' बना दिया, यह उसी क्षमता का उदाहरण है।"

बिहारः क्या सरकारी नौकरी ही है एक विकल्प

▪ मनीष कुमार

कई युवाओं को लगता है कि सरकारी नौकरी में सरकारी सुविधाओं के साथ जीवन आराम से कट जाएगा। ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लाखों छात्र घर से दूर शहरों की छोटी कोठरियों में अपनी युवावस्था के अनगिनत साल लगा देते हैं।

बिहार की राजधानी पटना के रमना रोड से जुड़ी एक तंग गली। इसी गली के एक स्टूडेंट लॉज के एक कमरे में पढ़ रहे मो। मुबारक हुसैन। चेहरे पर चिंता की लकीरें। हाल पूछते ही कहते हैं, "क्या बताऊं, सोचा था कि इस बार बीपीएससी (बिहार लोक सेवा आयोग) का प्रीलिम्स (पीटी) क्लियर हो जाएगा। लेकिन, लगता है नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इस बार भी रह ही जाएंगे। तब तो घर लौटने के सिवा कोई उपाय नहीं रह जाएगा।"

कटिहार निवासी हुसैन इंटर की परीक्षा पास करने के बाद प्रशासनिक अधिकारी बनने की महत्वाकांक्षा के साथ आज से करीब 14 वर्ष पहले पटना आए थे। प्रतिष्ठित पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर पटना विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हुए। फिर बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा की तैयारी में जुट गए, ताकि एसडीओ-एसडीपीओ बन सकें। अपनी ओर से सौ फीसद देने के बावजूद आज तक उनका सपना पूरा नहीं हो सका है। इस बीच एसएससी (स्टाफ सेलेक्शन कमीशन) द्वारा ली जाने वाली ग्रेजुएशन लेवल (सीजीएल) की भी परीक्षाएं दीं। किंतु, कभी पेपर लीक तो कभी विलंब से परीक्षा लिए जाने या फिर रद्द हो जाने की वजह से उनका सफर आज भी जारी है। इस बीच लंबा अरसा बीत जाने से उन पर सामाजिक-आर्थिक दबाव बढ़ गया है।

बातचीत में वो कहते हैं, "पहले तीन-साढ़े तीन हजार रुपये में काम चल जाता था, लेकिन अब तो सात-साढ़े सात हजार में भी काम नहीं चलता। इसके बावजूद किन हालातों में रह रहा हूं, यह आप देख ही रहे हैं। पिता किसान हैं, और भी भाई-बहनें हैं। आखिर, कब तक वे पैसा भेजते रहेंगे।" हुसैन का आठ गुणा दस फीट का कमरा है, इसी में दो लोग रहते हैं। कमरे में पुस्तकों का अंबार और अन्य सामान भी। बाहर खाना बनाना पड़ता है, सुबह बाथरूम-टॉयलेट में लाइन लगानी पड़ती है। परीक्षा के कारण खाना बनाना फिलहाल बंद है। फिर भी वे पूरे जोर-शोर से लक्ष्य प्राप्ति का हर संभव प्रयास कर रहे।

सता रही करियर की चिंता

प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी का इतना लंबा समय बीत गया और अब अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, यह पूछने पर हुसैन बेबाक कहते हैं, "आयोग अब अयोग्य हो गया है। मैं 67वीं पीटी से अटेम्प्ट ले रहा हूं, क्या ये परीक्षाएं विवादित नहीं रहीं? इस बार अगर बीपीएससी का री-एग्जाम नहीं हुआ तो पढ़ाई अब छोड़नी ही पड़ेगी। कटिहार लौट कर कोचिंग संस्थान खोलूंगा, और क्या विकल्प है मेरे पास। हालांकि, यहां से लौट कर वहां जाना इतना आसान नहीं है।"

वहीं, छात्र नेता नीरज यादव कहते हैं, "मैं बीपीएससी की 67वीं पीटी देने जा रहा था। मेरा सेंटर कैमूर में पड़ा था। जिस ट्रेन में मैं था, उसी में निचले बर्थ पर एक और लड़का था। अचानक वह ऐसे रोने लगा, जैसे उसके परिवार में कोई बड़ी घटना हो गई हो। पूछने पर उसने कहा, पेपर लीक हो गया है, अब क्या होगा। खैर।।। मैंने उसी दिन तय कर लिया कि अब यह परीक्षा फिर नहीं दूंगा।"

हाल के सालों में कई बार नौकरी की परीक्षाओं में तो सेटिंग की खबरें आम हो चुकी हैं। नीट-यूजी का पेपर लीक हुआ, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे सॉल्वर पकड़े गए। छात्रों की मांग है कि जहां भी सरकारी वैकेंसी है, उसे ईमानदारी से भरा जाए, फेयर एक्जाम लिए जाएं, परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। इसके अलावा वे चाहते है कि जहां भी नॉर्मलाइजेशन के कारण प्राप्त परसेंटाइल का इस्तेमाल हो, उसके बारे में भी अभ्यर्थी को पूरी तरह बताया जाए।

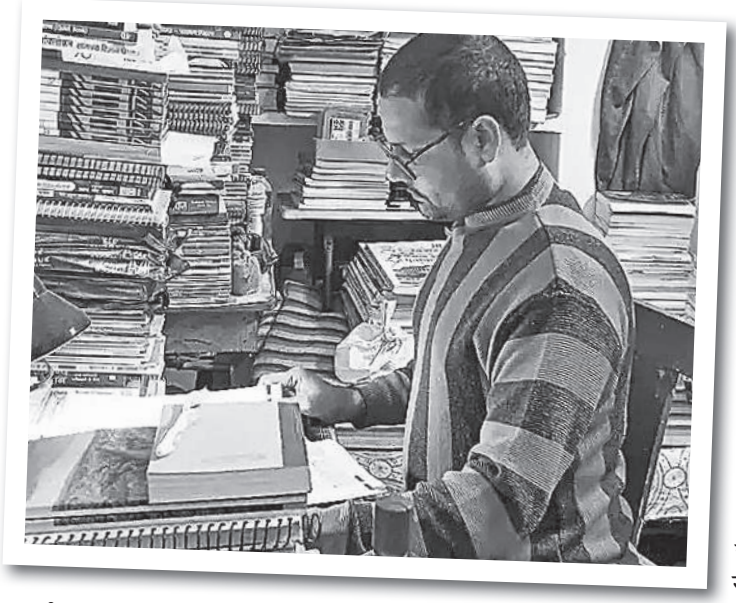

सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी

सरकारी ही क्यों, प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं, यह पूछने पर वे और उनके कुछ मित्र एक साथ बोल उठते हैं, "सरकारी नौकरी में सामाजिक प्रतिष्ठा है, स्टेटस सिंबल है। माता-पिता भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। सिक्योरिटी है, जब तक कि आप कुछ गलत न करें। भरोसा है कि तमाम तरह की सरकारी सुविधाओं के साथ जीवन आराम से कट जाएगा। बताइए, प्राइवेट नौकरी का ऐसा भरोसा है क्या। पता नहीं, कब क्या कह कर निकाल दिए जाएं।"

जिनसे भी बात कीजिए, ज्यादातर युवाओं को लगता है कि प्राइवेट जॉब में पूरा जीवन डरे-सहमे और पसोपेश में गुजर जाता है। आपको हमेशा अपनी उपयोगिता साबित करनी पड़ती है, स्वयं को अपडेट करना होता है। कोई कहता है कि कोविड काल में कैसे बड़ी-बड़ी कंपनियों तक ने लोगों को नहीं बख्शा और लोग अर्श से फर्श पर आ गए।

उनका मानना है कि जीवन-यापन का और कोई साधन नहीं होने पर उन्हें भी प्राइवेट नौकरी करनी पड़ सकती है लेकिन वह भी उनकी शर्तों पर तो मिलेगी नहीं। कुछ छात्र कहते हैं कि इस बार भी 'बिहार बिजनेस कनेक्ट' में एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति होने की बात कही जा रही है, कई एमओयू हुए, लेकिन एक साल बाद देखिएगा कि इससे सचमुच कितने रोजगार का सृजन हुआ।

---पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हों परीक्षाएं

बिहार के लोगों की कर्मठता और श्रम शक्ति के भरोसे ही देश के कई राज्य दशकों से विकास की राह पर अग्रसर हैं। इतना ही नहीं, इस प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में पुलिस, प्रशासन व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवा दे रहे हैं। किंतु, इसके साथ ही यह भी कटु सत्य है कि यहां बढ़ती आबादी की तुलना में रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो सका है। इसलिए सरकारी नौकरी पर निर्भरता आज भी बरकरार है।

पत्रकार शिवानी सिंह कहती हैं, ''इसमें दो राय नहीं कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। किंतु, जो परीक्षा ले रही है उसे तो पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से संपन्न तो करवा ही सकती है।'' बीते सात साल में बिहार में 67वीं पीटी और नीट-यूजी समेत दस परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए, जिनकी जांच चल रही है। जाहिर है, पेपर लीक को लेकर अंदेशा भी बढ़ेगा और सवाल भी उठेंगे।

उद्योग-धंधे बिना पलायन ही उपाय

हुसैन बातचीत में कहते हैं, "आप ही बताएं यहां और क्या विकल्प मौजूद है। सरकारें आती हैं, नए-नए उद्योग-धंधे के शुरू होने की बातें होती हैं। कुछ योजनाएं तो फाइलों में ही रह जाती हैं और अगर कुछ शुरू भी हुईं तो बेरोजगारों की फौज के सामने वे ऊंट के मुंह में जीरा समान साबित होती हैं। काम की तलाश में पलायन तो इसी वजह से हो रहा ना। और फिर मेरी योग्यता के अनुसार काम अपने यहां मिल जाएगा, इसका क्या भरोसा।"

गुंजन कुमार सिन्हा ने निदेशक कार्मिक का पदभार ग्रहण किया

गुंजन कुमार सिन्हा ने 15 जनवरी, 2025 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) में निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया।गुंजन कुमार सिन्हा ने जुलाई 1994 में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीआईएल की एक सहायक कंपनी में कल्याण अधिकारी प्रशिक्षु के रूप में अपनी समर्पण यात्रा आरंभ की थी।

उनके पास जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस (एक्सआईएसएस), रांची से कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री और इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट (आईएसटीडी), नई दिल्ली से प्रशिक्षण और विकास में डिप्लोमा है। श्री सिन्हा ने ईएससीपी बिजनेस स्कूल, पेरिस में उन्नत प्रशिक्षण के माध्यम से अपने नेतृत्व और प्रबंधन कौशल को और निखारा है।

उन्होंने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की कई कोयला खदानों में 16 साल समर्पित किए, जहां उन्होंने कार्मिक और प्रशासन (पीएंडए) विभाग का नेतृत्व किया। इसके बाद उनकी पदस्थापना सतर्कता विभाग में रही, जहां उनका सेवाकाल सात साल का रहा और उन्होंने अनुशासनात्मक कार्यवाहियों और कानूनी मामलों का प्रबंधन किया।

उनका योगदान सीसीएल में भूमि और राजस्व अनुभाग के कानूनी प्रभाग में भी रहा। जनवरी 2022 में, श्री सिन्हा ने सीआईएल में कर्मठ एवं समर्पित कार्यबल में सतत संवर्धन के लिए कंपनी के भर्ती प्रभाग के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला और अधिकारियों की भर्ती का सुप्रबंधन किया।

संगठनात्मक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अगले क्रम में, उन्होंने मई 2024 से मानव संसाधन विकास प्रभाग के प्रमुख के रूप में अतिरिक्त दायित्व ग्रहण किया और कोल इंडिया लिमिटेड की कर्म शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए उनका कौशल एण्ड प्रतिभा विकास किया।

कोल इंडिया लिमिटेड में उनके लगभग 31 वर्षों के विशाल अनुभव से निश्चित रूप से न केवल ईसीएल बल्कि पूरे कोयला उद्योग को लाभ होगा।

एनएमडीसी व केआईओसीएल के मर्जर को लेकर अपडेट

एनएमडीसी और कुद्रमुख आयरन ओर कंपनी (केआईओसीएल) के मर्जर की खबरों को लेकर अब एक बड़ा अपडेट आया है। नवरत्न पीएसयू एनएमडीसी ने स्पष्ट किया है कि कथित ' एनएमडीसी - केआईओसीएल मर्जर ' के संबंध में 'कोई बातचीत नहीं हुई है'। एक्सचेंज फाइलिंग में एनएमडीसी ने स्पष्ट किया कि कंपनी को एनएमडीसी लिमिटेड और केआईओसीएल लिमिटेड के विलय के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है।

एक्सचेंज फाइलिंग के जरिये एनएमडीसी ने केआईओसीएल के साथ विलय को अफवाह करार देते हुए कहा, "...यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉर्पोरेट विलय से संबंधित मामला स्टील मंत्रालय के अधीन है और वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईएपीएम) से परामर्श के बाद ही आगे का फैसला लिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी को एनएमडीसी लिमिटेड और केआईओसीएल लिमिटेड के विलय के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है।"

कंपनी ने आगे सूचित किया, "...कंपनी के पास सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 30 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा करने के लिए कोई मूल्य संवेदनशील जानकारी/घोषणा नहीं है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड पर लें। कृपया हमें बताएं कि क्या इस संबंध में किसी और स्पष्टीकरण/सूचना की आवश्यकता है।"

इससे पहले खबरें आ रही थीं कि स्टील मंत्रालय मर्जर के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। पूरे आकलन के बाद प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। हालांकि,केआईओसीएल माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने को लेकर कई तरह की समस्या का सामना कर रही है। ऐसे में एनएमडीसी और केआईओसीएल का मर्जर दोनों कंपनियों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। लिहाजा, सरकार इस बार की संभावना तलाश रही है कि क्या एनएमडीसी और केआईओसीएल का मर्जर किया जाए।

कोलकता: बलात्कार-हत्याकांड के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त, 2024 को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी को अदालत ने सजा सुना दी है.

कोलकाता की सियालदह अदालत के बाहर सुबह से ही गहमागहमी थी, अदालत से कुछ दूरी पर दर्जन भर लोग दोषी 33 साल के संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे. पुलिस ने हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई को लेकर पुख्ता इंतजाम किए थे और अदालत परिसर के बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे.

9 अगस्त, 2024 को हुई दिल दहलाने वाली घटना में सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष जज अनिर्बान दास ने अपने फैसले में कहा कि यह जघन्यतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता, कोर्ट ने दोषी को मौत तक उम्रकैद की सजा देने का फैसला किया. जज दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने दोषी को मौत की सजा की मांग की थी. अदालत ने रॉय को 18 जनवरी को दोषी करार दिया था.

अदालत ने रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 और 103 (1) के तहत दोषी ठहराया था. फैसला सुनाते हुए जज अनिर्बान दास ने कहा कि सीबीआई ने यौन शोषण और बलात्कार के जो सबूत पेश किए हैं, उनसे रॉय का अपराध साबित होता है.

ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हुए थे और दो महीने से ज्यादा समय तक राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रहीं. इस मामले ने भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए थे. देश के अलग-अलग शहरों के अलावा विदेश में भी पीड़िता को इंसाफ देने के लिए प्रदर्शन हुए थे.

सियालदह अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया. सजा सुनाए जाने से पहले रॉय ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे फंसाया जा रहा है. टाइम्स ऑफ इंडिया ने अदालत की कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रॉय ने अदालत से कहा, "मैंने कुछ नहीं किया, ना ही बलात्कार, ना ही हत्या. मुझे झूठा फंसाया जा रहा है. आपने सब कुछ देखा है.

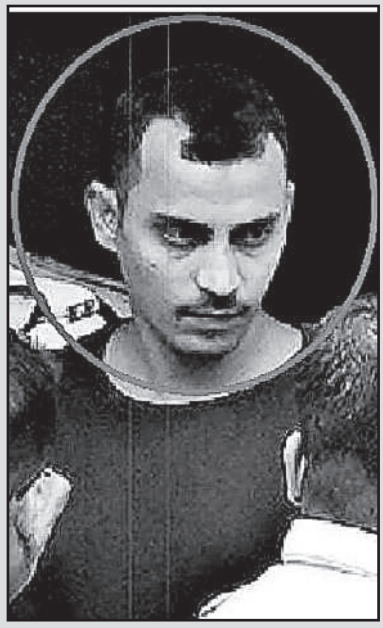

मैं निर्दोष हूं. मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे प्रताड़ित किया गया. उन्होंने मुझसे जो चाहा, उस पर हस्ताक्षर करवाए."

सजा सुनाए जाने से पहले रॉय के वकील ने मौत की सजा के खिलाफ तर्क दिया था कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि रॉय "सुधार के लायक नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए." सीबीआई ने अदालत से रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए कहा था कि वह समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं, वहीं पीड़िता के माता-पिता ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग थी. सीबीआई ने अपनी जांच में 120 गवाहों के बयान दर्ज किए थे और उसने अपनी जांच में पाया था कि पीड़िता की मौत गला घोंटने से हुई थी.

सजा सुनाये जाने के बाद पीड़िता के माता-पिता ने मीडिया से कहा है कि वे दोषी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि जांच अधूरे मन से की गई और अपराध में शामिल कई और दोषियों को बचाया गया. उन्होंने कहा कि वे इंसाफ के लिए हाई कोर्ट जाएंगे.

पीड़िता की मां ने कहा, "हम स्तब्ध हैं. यह दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम क्यों नहीं है? ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. हम निराश हैं. इस अपराध के पीछे एक बड़ी साजिश थी." पीड़िता के पिता ने कहा कि जब तक सभी दोषियों को सजा नहीं जाती वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 9 अगस्त, 2024 को 31 वर्षीय महिला डॉक्टर का शव मिलने के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के आरोप में संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था. देशभर के डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बाद मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था.

महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद देशभर के कई शहरों में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की थी, जिससे चिकित्सा सेवाएं बाधित हुईं. महिला डॉक्टर के साथ जो अपराध हुआ उसके विरोध में आम लोग भी सड़क पर उतर आए और पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग की.

महिलाओं के खिलाफ हिंसा भारत की एक बड़ी समस्या है. 2022 में औसतन हर दिन 90 बलात्कार के मामले दर्ज हुए. बहुत से लोग कोलकाता की घटना की तुलना 2012 के निर्भया कांड से कर रहे हैं. एक तथ्य यह भी है कि बलात्कार जैसे अपराधों के कम ही मामलों में दोष साबित होता है या फिर दोषी को सजा मिलती है.

केंद्र सरकार ने कई तरह के नए अपराधों की श्रेणी बनाई है और इसमें छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराध भी शामिल हुए हैं. यहां तक कि मामला दर्ज करने में आनाकानी या फिर इसके लिए मना करने वाले अधिकारियों को भी जेल भेजा जा रहा है.

साल 2023 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ओर से जारी सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 के मुकाबले 2022 में महिलाओं के प्रति अपराध में चार प्रतिशत का इजाफा हुआ. देश में अपराध के 58 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिनमें महिलाओं के प्रति अपराध के करीब साढ़े चार लाख मामले थे. मतलब हर घंटे औसतन करीब 51 एफआइआर दर्ज हुई.

पढ़े-लिखे बच्चों व परिवारों में रह रहे बुजुर्ग ही वृद्धाश्रम भेजे जाते हैं

▪ रामांशी मिश्रा

पूरे भारत में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्हें अपने बुढ़ापे में या तो वृद्धाश्रम या समाजसेवियों का सहारा लेना पड़ता है। जो गिने चुने समाजसेवी ऐसी सेवा में लगे हैं, खुद उनके हिस्से भी कई परेशानियां आती हैं।

वाराणसी के श्रीनाथ खंडेलवाल उन साहित्यकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में मत्स्य पुराण, पद्म पुराण समेत 400 से ज्यादा पुस्तकें लिखीं। उन्हें यश और वैभव दोनों ही मिले। 2024 तक करोड़ों की संपत्ति के मालिक श्रीनाथ खंडेलवाल को अपने जीवन का आखिरी चरण एक वृद्धाश्रम में बिताना पड़ा। मार्च 2024 में परिवार ने उनसे किनारा कर लिया और तब काम आए समाजसेवी अमन कबीर। 28 दिसंबर को खंडेलवाल की मृत्यु के बाद भी जब उनके घरवाले नहीं पहुंच सके, तब उनकी अंत्येष्टि प्रक्रिया भी अमन ने ही पूरी की। लेकिन उसके बाद खंडेलवाल के परिवार ने अमन पर मानहानि का मामला दर्ज करवा दिया और यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है।

श्रीनाथ खंडेलवाल की तरह लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाले एक पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बेटियों की भी हालत रही। माता-पिता की मृत्यु के बाद उनकी दो अविवाहित बेटियों राधा और मुन्नी को परिवारजनों ने मरने के लिए छोड़ दिया। वर्षों तक उनकी किसी ने सुधि नहीं ली। फिर किसी ने समाजसेवी वर्षा वर्मा को उनके बारे में बताया। वर्षा ने जब उनकी मदद की तो कुछ लोगों ने राधा और मुन्नी का अपहरण करने की कोशिश की। वर्षा तब भी उनके साथ रहीं, लेकिन मुन्नी अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाईं। इसके बाद राधा का अपहरण करने में भी लोगों को सफलता मिल गई और उनका आजतक पता नहीं चल पाया। देश के अलग-अलग कोनों में अमन कबीर और वर्षा वर्मा जैसे कई ऐसे समाजसेवी हैं जो खंडेलवाल, राधा और मुन्नी जैसे कई लोगों को सहारा देते हैं।

श्रद्धा और सहयोग साथ-साथ

मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले 30 साल के अमन पिछले 15 वर्षों से वाराणसी में समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने सरकारी अस्पतालों के बाहर लावारिस पड़े रहने वाले मरीजों की सेवा से की। एक फाइलेरिया के मरीज की पट्टी करते वक्त एक परिचित ने अमन की फोटो खींचकर फेसबुक पर डाल दी और उसके बाद से अमन को ऐसे लोगों से जुड़े कई फोन आने लगे।

वाराणसी हमेशा से श्रद्धालुओं से भरा शहर रहा है। अमन न केवल वाराणसी के रहने वाले लोगों की मदद करते हैं बल्कि अब तक वह हजारों खोए हुए लोगों को वाराणसी से सकुशल घर पहुंचा चुके हैं। डीडब्ल्यू से

अमन ने बताया, "कई बार श्रद्धालु यहां तक आते हैं और कभी बीमारी या फिर किसी कारण से खो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनकी देखरेख करने को कोई नहीं होता।" अमन अब तक 19 राज्यों के लोगों को सकुशल उनके घर तक पहुंचा चुके हैं। अमन बताते हैं, "एक बार एक लड़का शिवलिंग पर अपनी बलि देने आ गया। चाकू लगते ही गर्दन से खून निकलने लगा। मंदिर के प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती तो कराया लेकिन उसके बाद उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। उसकी देखरेख के लिए मैं आगे आया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया तो तमिलनाडु से उसके घर वाले यहां लेने के लिए पहुंचे।"

अमन की तरह लखनऊ में वर्षा 14 साल की आयु से समाज सेवा कर रही हैं और बीते सात वर्षों से लखनऊ की अलग-अलग जगहों पर मिलने वाले लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती हैं। इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है। वर्षा कहती है, "लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करना आसान नहीं होता। शव मिलने पर पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद 72 घंटे तक उसे शिनाख्त के लिए रखा जाता है, पहचान की नोटिस चस्पा की जाती है। इसके बाद भी यदि बॉडी क्लेम के लिए कोई नहीं आता तो वह शव हमें दिया जाता है। कई बार शव इतनी बुरी हालत में होते हैं कि उनका अंतिम संस्कार कर पाना मुश्किल होता है।" इन सात वर्षों में वर्षा 6,000 से भी अधिक अंत्येष्टि संस्कार कर चुकी हैं।

बुजुर्गों के साथ मरीजों की भी मिलती है दुआ : अमन ने कई वर्षों पहले वाराणसी में पहली बार 'बाइक एंबुलेंस' शुरू की। इसका कारण बताते हुए अमन कहते हैं, "कई ऐसे भी इलाके हैं जहां चार पहिए की गाड़ी नहीं पहुंच पाती, लेकिन बीमार तो लोग वहां भी होते हैं। इसके अलावा कई बार ट्रैफिक जाम में फंसकर लोगों को इलाज मिलने में देरी हो जाती है। ऐसे में बाइक ऐसा साधन बनता है जो दोनों ही परिस्थितियों में सुलभ है।" वर्षा भी लखनऊ के अस्पतालों से गरीब मरीजों को एंबुलेंस से उनके घर तक निशुल्क भेजती हैं। इसके अलावा जिन लावारिस शवों की पहचान हो जाती है, उनके परिवार को शव घर तक ले जाने के लिए शव वाहन का इंतजाम करवाती हैं। वर्षा कहती हैं, "मुझे भी सीखने में समय लगा। पुरुष प्रधान समाज में खुद को खड़ा कर पाना भी मेरे लिए मुश्किल था। एक लड़की होने के नाते इस तरह के काम करने पर रिश्तेदारों और समाज के कई मापदंडों पर मेरे लिए प्रश्न चिन्ह थे। उन सभी को पार कर अपने परिवार के समर्थन से आज भी अपना काम निस्वार्थ भाव से कर रही हूं।"

परेशानियों से होते हैं दो चार

वर्षा बताती हैं कि एक परिवार में पांच लड़कियों के पिता की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी उनके पास आई। बच्चियों की मां की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। पिता के अंतिम संस्कार के समय आसपास के लोगों ने अंतिम संस्कार के दौरान कई तरह के सवाल जवाब किए। परेशानी यही खत्म नहीं हुई। अंतिम संस्कार के बाद पांचों लड़कियां घर से गायब हो गईं और तब वर्षा सवालों के घेरे में आ गई। पुलिस के सवाल जवाब के साथ मीडिया और आसपास के लोगों ने भी विरोध करना शुरू किया। एक स्थानीय चैनल ने वर्षा पर अंग तस्करी का आरोप लगाया। वर्षा ने खबर का विरोध किया तो न्यूज चैनल ने कहा कि इस खबर से उनकी टीआरपी बढ़ गई है इसलिए सच न हो तो भी वह खबर वापस नहीं लेंगे। आखिरकार कुछ दिनों बाद यह पता चला कि बच्चियों को उनके कुछ रिश्तेदार बिना बताए गांव लेकर चले गए थे। वर्षा कहती हैं, "सुरक्षा के साथ-साथ कई बार हमें उन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है जिसमें हमारी अच्छाइयों और सेवा पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं।"

वहीं अमन बताते हैं कि कई बार अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए परिवार ही खड़ा नहीं होता। हम जी जान से सेवा करते हैं। दुर्भाग्य से अगर मरीज की मृत्यु हो जाए तो लोग हम पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। लोग किसी व्यक्ति को भर्ती करवाने या वृद्धाश्रम पहुंचाने या फिर अपने मतलब के लिए हमें फोन करते हैं। इसके अलावा आज भी आसपास कई ऐसे लोग हैं जो किसी ने किसी बहाने व्यंग्य करते हैं या कमी निकालने की कोशिश करते हैं।" कोरोना काल में नवजात बच्चों को दूध पहुंचाने से लेकर घर के द्वारा त्यागे गए कई कोरोना संक्रमित लोगों के शवों का अंतिम संस्कार अमन ने किया।

श्री श्री परमहंस योगानन्द की स्थायी विरासत

"हमारा संसार एक स्वप्न के अन्दर एक स्वप्न है; आपको यह अनुभव करना चाहिए कि ईश्वर-प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है जिसके लिए आप यहां हैं।" — श्री श्री परमहंस योगानन्द।

▪ रेणु सिंह परमार

प्रिय गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानन्द प्रायः कहा करते थे कि मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य ईश्वर की खोज करना है। अन्य सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है परन्तु ईश्वर की खोज नहीं।

योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में धर्मनिष्ठ बंगाली माता-पिता ज्ञान प्रभा और भगवतीचरण घोष के परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था। जब ज्ञानप्रभा अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के पास अपनी गोद में शिशु मुकुन्द को लेकर गई, तो महान् संत ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, "छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन की भाँति वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के राज्य में ले जाएगा।" कालान्तर में यह पवित्र भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई।

बचपन में मुकुन्द माँ काली से गहन प्रार्थना और ध्यान किया करते थे। ऐसे ही एक अवसर पर, वे एक गहन दिवास्वप्न में डूब गए और उनकी अन्तर्दृष्टि के सामने एक प्रखर प्रकाश कौंध गया। वे इस दिव्य प्रकाश को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा, "यह अद्भुत् आलोक क्या है?" उन्हें इस प्रश्न का एक दैवी प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ, "मैं ईश्वर हूँ। मैं प्रकाश हूँ।" योगानन्द जी ने अपनी पुस्तक "योगी कथामृत" में इस अलौकिक अनुभव का वर्णन किया है, "वह ईश्वरीय आनन्द क्रमशः क्षीण होता गया पर मुझे उससे ब्रह्म की खोज करने की प्रेरणा की स्थायी विरासत प्राप्त हुई।"

सन् 1910 में, सत्रह वर्ष की आयु में, उन्होंने अपनी ईश्वर की खोज की आध्यात्मिक यात्रा प्रारम्भ की। यह खोज उन्हें उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के पास ले गई। अपने गुरु के प्रेमपूर्ण परन्तु कठोर मार्गदर्शन में, उन्होंने स्वामी परम्परा के अन्तर्गत पवित्र संन्यास का आलिंगन किया। वे अपने सन्यासी नाम परमहंस योगानन्द से प्रसिद्ध हुए, जो ईश्वर के साथ एकत्व के माध्यम से सर्वोच्च आनन्द की प्राप्ति का प्रतीक है।

उन्होंने सन् 1917 में रांची में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ़ इण्डिया (वाईएसएस) और सन् 1920 में लॉस एंजेलिस में सेल्फ़-रियलाइज़ेशन फ़ेलोशिप (एसआरएफ़) की स्थापना की। इन दोनों संगठनों का प्राथमिक उद्देश्य है जीवन के परम उद्देश्य—अर्थात् आत्मा का परमात्मा से साथ एकत्व—को साकार करने के लिए "क्रियायोग" ध्यान प्रविधियों के प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान का प्रसार करना। आकांक्षी साधक योगदा सत्संग आश्रमों से अनुरोध करके गृह-अध्ययन पाठमाला के रूप में स्वयं महान् गुरुदेव द्वारा प्रदान की गयी इन पवित्र शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं।

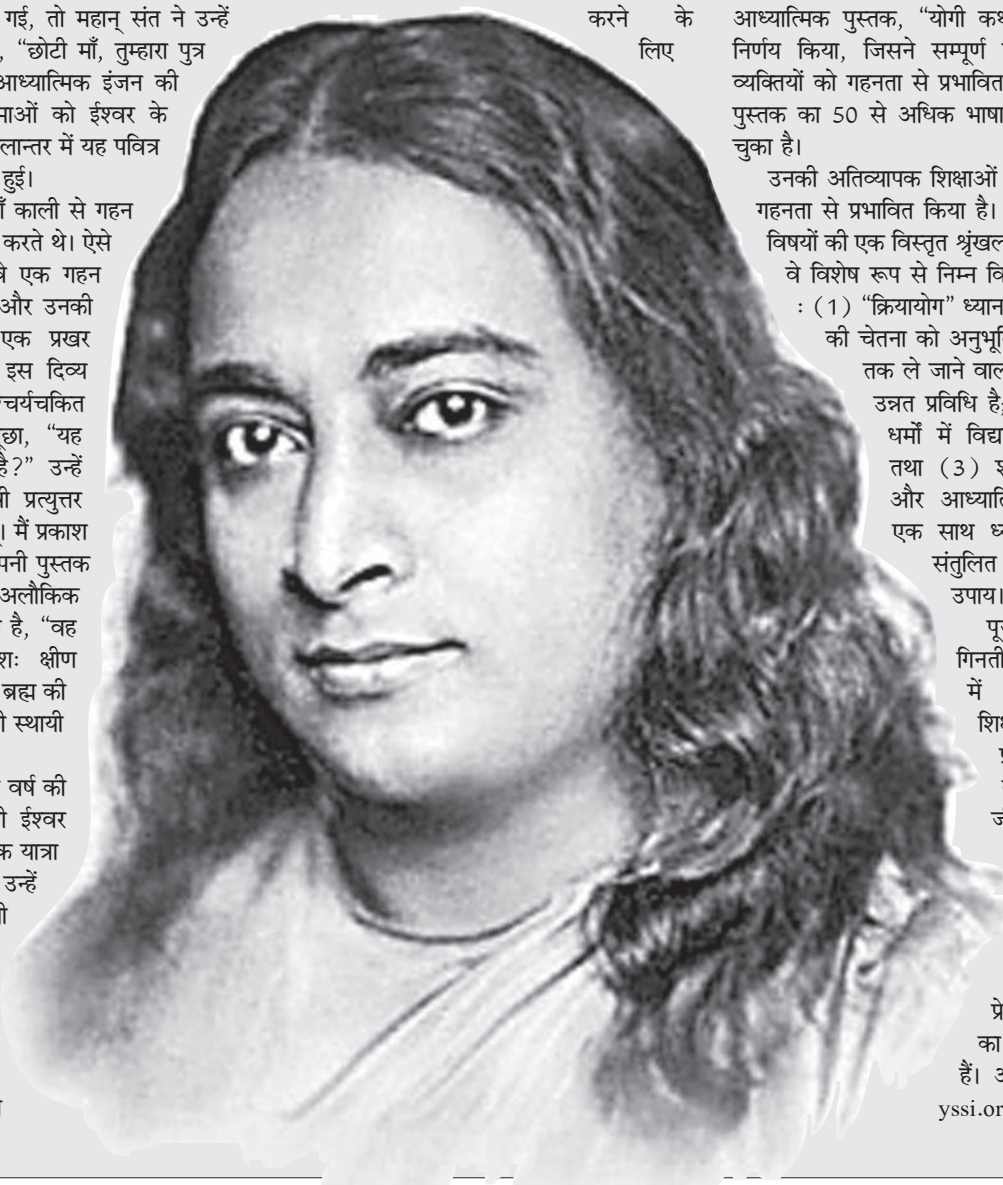

योगानंद जी ने अमेरिका में रहते हुए उपरोक्त भारतीय आध्यात्मिक साधना के ज्ञान के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न किया, जिसका अत्यधिक स्वागत किया गया और सराहना की गयी। ईश्वर की अपनी खोज को सबके साथ साझा करने की लालसा से प्रेरित होकर उन्होंने अत्यन्त प्रसिद्ध एवं अति उत्कृष्ट आध्यात्मिक पुस्तक, "योगी कथामृत" लिखने का निर्णय किया, जिसने सम्पूर्ण विश्व में असंख्य व्यक्तियों को गहनता से प्रभावित किया है और इस पुस्तक का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।

उनकी अतिव्यापक शिक्षाओं ने लाखों लोगों को गहनता से प्रभावित किया है। उनकी शिक्षाओं में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है तथा वे विशेष रूप से निम्न विषयों पर केन्द्रित हैं : (1) "क्रियायोग" ध्यान विज्ञान, जो मनुष्य की चेतना को अनुभूति के उच्चतर स्तरों तक ले जाने वाली राजयोग की एक उन्नत प्रविधि है; (2) सभी सच्चे धर्मों में विद्यमान गहन एकता; तथा (3) शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को एक साथ ध्यान में रखते हुए संतुलित जीवन जीने के उपाय।

पूज्य जगद्गुरु की गिनती अब सम्पूर्ण विश्व में प्राचीन भारतीय शिक्षाओं के सबसे प्रभावशाली दूतों में की जाती है। उनका जीवन और शिक्षाएं सभी क्षेत्रों तथा सभी जातियों, संस्कृतियों, और मतों के व्यक्तियों के लिए प्रेरणा एवं उत्साह का एक शाश्वत स्रोत हैं। अधिक जानकारी : yssi.org

हॉकी की सूरमा और टीम के भरोसे का आधार सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार

▪ चंचल भट्टाचार्य

कोई खेल केवल खेल नहीं होता और ना ही हॉकी, केवल हॉकी है. अर्थात हॉकी, खेल के साथ-साथ और भी बहुत कुछ है. हॉकी जीवन है. हॉकी, आशा, भरोसा और विश्वास भी है. लेकिन इसके साथ ही, अपनी कमजोरी और कठिनाइयों के साथ-साथ, सभी बाधाओं को पार कर किस प्रकार से उपलब्धियाँ प्राप्त की जा सकती है... इसका प्रमाण भी हॉकी और इसके खिलाड़ी हैं.

झारखंड के सिमडेगा जिले के बड़की छापर गाँव की रहने वाली सलीमा टेटे ने अपने जीवन में व्याप्त कठिनाइयों और बाधाओं को सामने देखकर शायद ही कभी सोचा होगा कि वह हॉकी के अंतरराष्ट्रीय फलक पर न केवल अपना या अपने परिवार का बल्कि, अपने झारखंड और देश का मान भी इस तरीके से रोशन कर पायेंगी. अपने मजबूत व्यक्तित्व और धैर्य के बलबूते अपने सपनों को पूरा करने का उन्हें भरोसा तो था, तभी तो उन्होंने बड़े सपने देखे और जी-जान लगा दी. लेकिन फिर भी शायद आज सलीमा को भी यह किसी करिश्माई कहानी की तरह ही लगती होगी जब हॉकी इंडिया की कप्तान सलीमा टेटे के नाम आज वैसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिस पर देश और हॉकी इंडिया गर्व कर सकता है.

सलीमा टेटे, झारखण्ड की वैसी पहली महिला अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया. उनके साथ 31 अन्य खिलाड़ियों को भी अर्जुन पुरस्कार एवं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इससे पहले झारखंड के हॉकी ओलम्पियन माइकल किंडो को 1972 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

वास्तव में, अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के बलबूते सलीमा टेटे ने जो उपलब्धियाँ प्राप्त की है वह न केवल झारखण्ड या यहाँ के हॉकी खिलाड़ियों बल्कि संपूर्ण खेल जगत के साथ-साथ सभी खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है.

...और जब सलीमा की बात चल ही रही है तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अभी रांची में जारी पहली महिला हॉकी इंडिया लीग में उस सूरमा हॉकी क्लब का बहुत बड़ा आधार वह सलीमा टेटे ही हैं जो इसकी कप्तान हैं और इस लीग के शुरू होने के एक सप्ताह बाद अंक तालिका में सबसे ऊपर है.

रांची में पिछले 12 जनवरी 2025 को आरम्भ महिला हॉकी लीग के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रांची की छवि हॉकी के मामले में पहले से ही स्वर्णिम रही है. इससे पहले भी रांची अनेक अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धाओं की मेजबानी कर चुका है. विशेष रूप से पिछले वर्ष से 2024 में झारखंड में राजधानी रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुण्डा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में ही भारत की मेजबानी में ओलंपिक क्वालीफायर मैच का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में अमेरिका, जर्मनी, जापान, चिली, चेक रिपब्लिक, इटली, न्यूजीलैंड के साथ ही शीर्ष वरीयता क्रम में दुनिया की छठे नंबर की टीम मेजबान भारतीय टीम ने भाग लिया. इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त तीन देशों ने पेरिस में 2024 में होनेवाली ओलंपिक में भाग लेने का टिकट पक्का किया. बहुत हद तक अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही और शीर्ष तीन स्थान में अपने-आपको कायम करने से चूक गयी.

रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ही 2024 में झारखंड वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का भी आयोजन किया गया जिसमें 6 देश की महिला हॉकी खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया. रांची में पहली बार आयोजित इस टूर्नामेंट में हांगझोऊ एशियाई खेल के चैंपियन चीन और रजत पदक हंगरी के साथ ही मलेशिया, जापान और मेजबान भारत ने भाग लिया और सबसे दिलचस्प स्थिति यह रही कि भारतीय टीम न केवल चैंपियन बनी बल्कि सभी मुकाबले में वह अपराजेय रही और उसने इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों को पराजित किया.

30 अप्रैल से 9 मई 2024 तक भारत में महिलाओं के लिये राष्ट्रीय महिला घरेलू हॉकी लीग का आयोजन भी इसी स्टेडियम में किया गया. पहली नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024-25 की मेजबानी का मौका झारखंड को मिला जिसमें 14 वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2024 की शीर्ष आठ महत्वपूर्ण हॉकी टीम ने भाग लिया. इसमें हॉकी हरियाणा, हॉकी महाराष्ट्र, हॉकी मध्य प्रदेश, हॉकी बंगाल, हॉकी मिजोरम, मणिपुर हॉकी और हॉकी एसोसिएशन ऑफ़ ओडिशा के साथ ही मेजबान हॉकी झारखंड की टीम शामिल है. इस लीग की मेजबानी भी अपेक्षा से कहीं अधिक उपलब्धियों से भरा रहा. इसके बाद अब महिला एचआईएल के स्वरूप में एक और उपलब्धि इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के खाते में दर्ज हो रही है.

हॉकी का यह महत्वपूर्ण मुक़ाबला, पूरे प्रोफेशनलिज्म अंदाज़ में आयोजित है जिससे कुल मिलाकर भारतीय हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मजबूत, सशक्त, लड़ाकू और जिताऊ टीम के रूप में बदलने का ऐसा मजबूत प्रयास है जिसके पूरी तरह से कामयाब रहने का पूरा विश्वास है.

महिला युवा खिलाड़ियों को निखारने और उन्हें अपना खेल विकसित करने का अवसर प्रदान करने की

दिशा में यह हॉकी इंडिया का एक महत्वपूर्ण कदम है. झारखण्ड के परिप्रेक्ष्य में विशेष बात यह भी है कि राज्य में हॉकी का गढ़ अब और भी मजबूत बन रहा है. पहली बार आयोजित इस लीग से न केवल झारखण्ड बल्कि देश में महिला हॉकी सुदृढ़ होगी साथ ही ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को प्रेरणा भी मिलेगी.

झारखण्ड में खेले जाने वाले सभी खेलों में प्रमुखः हॉकी के कारण ही पूरी दुनिया में झारखंड की पहचान है. चाहे बात मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के समय की हो या फिर आज की लेकिन एक बात सामान्य है जो दोनों ही स्थितियों में समान रूप से लागू होती है. तब भी झारखण्ड, हॉकी का गढ़ था और आज भी यही स्थिति है और यदि सटीक आकलन किया जाये तो आने वाले बरसों-बरस तक झारखंड की हॉकी की बादशाहत बरकरार रहेगी. झारखण्ड की नैसर्गिक प्रतिभाओं को उभारने, आगे बढ़ाने और पूरी दुनिया में अपने-आप को स्थापित करने के लिए ऐसी चैंपियनशिप सबसे अधिक प्रासंगिक है. ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाली भारतीय टीम में अनेक महिला खिलाड़ी झारखंड से ही होती हैं. आज हॉकी इंडिया की सबसे खास बात यह भी रही कि इसने मूल रूप से हॉकी की नर्सरी झारखण्ड, उड़ीसा जैसे प्रदेशों में अपने आधार को और भी मजबूत करने का प्रयास किया है. आज उड़ीसा और झारखंड, दो ऐसे प्रदेश हैं जो भारतीय हॉकी के परचम को पूरी दुनिया में फहराने की कुबत रखते हैं.

सूरमा हॉकी क्लब की कप्तान सलीमा टेटे के लिए यह घरेलू मैदान है और निश्चित रूप से यहाँ के दर्शकों का जबरदस्त समर्थन भी उन्हें मिल रहा है. लेकिन रांची में जैसी खेल भावना कायम है उसके कारण यह कहा जा सकता है कि यहाँ केवल अपनी टीम या सलीमा को समर्थन देने की बात नहीं है बल्कि टीम स्पर्धा हॉकी की प्रतिभावान और जुनूनी खिलाड़ियों के मामले में रांची का ऑडियंस बहुत अधिक पॉजिटिव है. भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी नवनीत कौर के शब्दों में रांची जैसा ऑडियंस और कहीं किसी दूसरी जगह पर नहीं मिलता क्योंकि यहाँ के लोग, हॉकी को वाकई में न केवल सम्मान देते हैं बल्कि खिलाड़ियों का उत्साह भी खुलकर बढ़ाते हैं. इससे पहले रांची में आयोजित एशियन चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालीफायर्स खेल चुकी नवनीत के शब्दों में रांची और झारखंड हॉकी के नेचुरल नर्सरी है. रांची में आयोजित महिला एचआईएल में चार टीम अपनी किस्मत आजमा रही है.

सूरमा हॉकी क्लब, दिल्ली एसजी पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स और श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स की टीम इस लीग पर अपने कब्जे के लिये अपना पूरा दम-ख़म लगा रही है.

12 जनवरी 2025 को रंगारंग कार्यक्रम के साथ आरम्भ महिला एचआईएल के उद्घाटन मैच में

ओडिशा वॉरियर्स ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 4-0 से हरा दिया. जेनसन ने 16 वें और 37 वें मिनट में गोल किया जबकि बलजीत कौर ने खेल के 42 वें और फ्रीके मोएस ने 43 वें मिनट में गोल कर अपनी टीम की बढ़त को बढ़ा दिया.

निश्चित रूप से रांची के इस अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में सूरमा हॉकी क्लब दर्शकों की सबसे फेवरेट

टीम है क्योंकि उसकी कप्तानी उसी सलीमा टेटे के हाथ में है जिन्होंने झारखंड और हॉकी का मान न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ाया है. 13 जनवरी को खेले गये अपने पहले मैच में सूरमा हॉकी क्लब ने श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स की टीम को 4-1 से हराया. मैच के फर्स्ट क्वार्टर में श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स का दबदबा रहा. मैच के 7 वें मिनट में ही हन्ना कॉटर के गोल से उसे 1-0 की बढ़त मिल गयी. इसके बाद सूरमा हॉकी क्लब की खिलाड़ी डिफेंस मोड में आ गयीं. सेकेंड क्वार्टर खाली गया लेकिन थर्ड क्वार्टर में सूरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ियों ने पूरे जोश में हल्ला बोला. फिर तो 38 वें मिनट में ओलिविया शैनॉन ने अपने गोल से अपनी टीम का खाता खोला. इसके बाद चार्लोट एंगलबर्ट ने 42 वें, कप्तान सलीमा टेटे ने 44 वें और सोनम ने 47 वें मिनट में लगातार गोल कार श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स की शिकस्त पक्की कर दी.

14 जनवरी को श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स का जुझारूपन सामने आया जब उसने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 1-0 से पराजित कर दिया. इस रोमांचक मुकाबले में बंगाल टाइगर्स की ओर से 23 वें मिनट में कैथरीन मुलान ने मैच का एकमात्र गोल किया और अपनी टीम को जीत दिलाकर अंक तालिका में ला दिया.

15 जनवरी को सूरमा हॉकी क्लब ने अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की जब उसने ओडिशा वॉरियर्स को 2-1 से हराया. सूरमा की ओर से हिना बानो ने 6 वें मिनट में पहला गोल किया जबकि सोनम ने 47 वें मिनट में आखिरी क्वार्टर में टीम की बढ़त को दोगुणा कर दिया. ओडिशा वॉरियर्स के लिये फ्रेके मोएस ने 57 वें मिनट में एकमात्र गोल कर केवल जीत के अंतर को कम किया लेकिन अपनी टीम की हार को टाल न सकी.

16 जनवरी को खेले गये मुकाबले में ओडिशा वॉरियर्स ने श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स की टीम को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया. ओडिशा वॉरियर्स की गोलकीपर जोसलीन बाट्राम के शानदार प्रदर्शन से निर्धारित समय तक दोनों टीम 1-1 से बराबर थी. ओडिशा वॉरियर्स के लिये बलजीत कौर से 8 वें मिनट में जबकि झारखण्ड की ब्यूटी डुंगडुंग ने 16 में मिनट में गोल दागा.

17 जनवरी को खेले गए मुकाबले में दिल्ली एसजी पाइपर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को 2-0 से हरा दिया. यह सूरमा हॉकी क्लब की इस लीग में पहली हार है. दिल्ली एसजी पाइपर्स के लिये झारखण्ड की संगीता कुमारी ने 25 वें और दीपिका ने 47 वें मिनट में गोल किया. हालांकि इस गोल को उतारकर जीतने के लिए सूरमा के खिलाड़ियों ने बहुत सारे प्रयास किये लेकिन वे असफल रहे. महिला एच आई एल का फाइनल मैच 26 जनवरी को रांची के इसी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेला जायेगा.

उधर पुरुषों का हॉकी इंडिया लीग 28 दिसम्बर 2024 को ओडिशा में राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में शुरू हुआ जिसके अधिकांश मैच यही खेले जाएंगे जबकि कुछ मैच का आयोजन रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में भी खेले जायेंगे.

पुरुषों की इस लीग में आठ टीम भाग ले रही है. तमिलनाडु ड्रेगन्स, श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स, हैदराबाद तूफ़ान्स, वेदांत कलिंगा लांसर्स, यूपी रुद्रस, सूरमा हॉकी क्लब, टीम गोनासिका और दिल्ली एसजी पाइपर्स में विजेता बनने की प्रतिस्पर्धा जारी है. फाइनल 1 फरवरी को राउरकेला में खेला जायेगा.

कुल मिलाकर हॉकी इंडिया लीग न केवल हॉकी प्रेमियों और प्रशंसकों बल्कि फ्रेंचाइजी टीमों के लिये भी रोमांचकता, चुनौती और तीव्र प्रतिस्पर्धा के साथ कदमताल कर रहा है जो हॉकी के लिये बहुत ही अच्छी बात है.

4 साल बाद सेलिब्रिटी मास्टरशेफ से दीपिका कक्कड़ का कमबैक

टीवी शो 'ससुराल सिमर का' में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ अब चार साल बाद टीवी पर वापसी कर रही हैं। जल्द ही दीपिका सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आएंगी। यह शो 27 जनवरी से सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होगा। हाल ही में इस शो को लेकर दीपिका ने दैनिक भास्कर से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अपनी वापसी को लेकर वह काफी एक्साइटेड हैं।

मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। जब मुझे कॉल आया कि एक कुकिंग शो आने वाला है क्या आप उसमें आएंगी, तो मैंने तुरंत हां कर दी। वैसे भी, मैं हमेशा से ही मास्टरशेफ की बड़ी फैन रही हूं। पहले मैं अकेली थी, तो किसी भी शो को करने से पहले ज्यादा नहीं सोचना पड़ता था। लेकिन अब मेरे पास बेटा रूहान है और चार साल से मैंने कोई शो नहीं किया तो शुरुआत में थोड़ी बहुत झिझक थी। हालांकि, मेरे पति शोएब ने मुझसे कहा कि शायद अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी सेकेंड इनिंग्स शुरू करनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूं। मुझे नहीं पता लेकिन मैं कभी भी रोने लगती हूं।

मैं दिल से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं। यह बात अब किसी को सही लगे या फिर गलत, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यकीन मानिए मैं दिल से बहुत साफ हूं। अगर मुझे कोई अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता और कोई लगता है तो फिर मैं हमेशा उसके लिए खड़ी रहती हूं। मैं हर चीज को बहुत ज्यादा दिल से जीती हूं। अभी तक मैंने जितने भी शो किए हैं।

पद्म पुरस्कार पर सोनू निगम ने उठाये सवाल

25 जनवरी को केंद्र सरकार ने पद्म अवॉर्ड्स विनर्स की घोषणा की। इसमें म्यूजिक की दुनिया के भी कई चेहरों का नाम शामिल है। गायक सोनू निगम ने अब इस पर सवाल उठाया है। सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस वीडियो को कैप्शन दिया है भारत और इसके लंबित पद्म पुरस्कार।

वीडियो में सोनू कहते हैं- 'दो ऐसे गायक जिन्होंने पूरी दुनिया के सिंगर्स को इंस्पायर किया है। एक को तो हमने पद्म श्री पर ही सिमटा दिया है। वो हैं मोहम्मद रफी साहब। एक हैं जिन्हें पद्म श्री भी नसीब नहीं हुआ है, किशोर कुमार जी। मरणोपरांत अवॉर्ड मिल रहा है ना। सोनू अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं- ' और जो हैं भी उनमें से अलका याग्निक जी का करियर इतना लंबा और कमाल का रहा। उन्होंने भी कुछ नहीं मिला है। श्रेया घोषाल बहुत समय से अपनी कला का लोहा मनवा रही हैं। सुनिधि चौहान ने अपनी अलग सी आवाज से पूरी जेनरेशन को इंस्पायर किया है। इन्हें भी अवॉर्ड नहीं मिला है।'

सैफ हमला केस में प. बंगाल से एक महिला गिरफ्तार

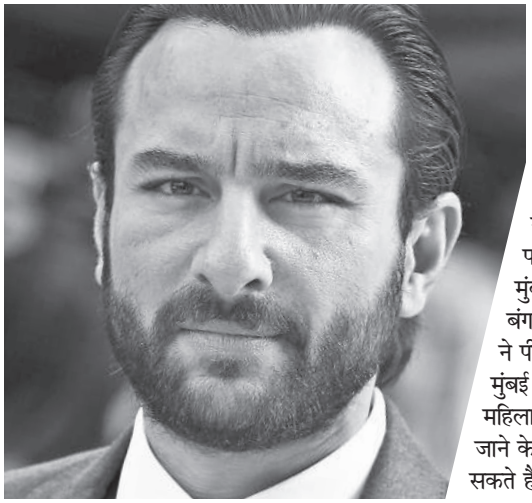

सैफ पर 15 जनवरी की देर रात हमला हुआ था। मुंबई पुलिस ने 22 जनवरी को फिंगरप्रिंट और अन्य सैंपल कलेक्ट करके सीआईडी की लैब में भेजे थे। हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट एक्टर के घर से लिए गए सैंपल से मैच नहीं हुए। जिसके बाद पुलिस जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

मुंबई पुलिस की दो सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल पहुंची। पश्चिम बंगाल पुलिस के सूत्र ने पीटीआई को बताया- "सैफ अली केस में मुंबई पुलिस ने नादिया जिले के छपरा से एक महिला को गिरफ्तार किया है। वे उसे मुंबई ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन कर सकते हैं।"

यह महिला सैफ केस में गिरफ्तार बांग्लादेशी शरीफुल इस्लाम को जानती थी।

पुलिस बोली , "शरीफुल ने उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी के पास भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था और इस महिला के संपर्क में आया था। वह वास्तव में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंदुलिया की निवासी है।"

फडणवीसबोले-जोबातेंपुलिसनेबोलीनहीं,वो दिखाई जा रहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा- सैफ अली खान केस में जो बातें पुलिस ने कही भी नहीं, उन बातों को बताकर मीडिया कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है जल्द ही इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा।

राशिफल

मेष इस माह आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप अपने कर्ज को भी चुका सकते है. आपको यात्राएं का भी सौभाग्य मिल सकता है. घरेलू जीवन प्रेम और उल्लास से भर रहेगा, लेकिन महीने के मध्य में झगड़े से सावधान रहें। शांत रहें, खुलकर संवाद करें और किसी भी भ्रम को बढ़ने से पहले ही दूर कर लें। याद रखें, धैर्य महत्वपूर्ण है ! संभावित लाभ और प्रगति के साथ व्यापार में तेजी आएगी।

मिथुन इस माह व्यवसाय शुरू करना लाभदायक हो सकता है, खासकर राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए ! हालांकि, अचानक नकदी खत्म होने से सावधान रहें जो आपकी जेब भरने से रोक सकती है। इससे उधार लेने की नौबत आ सकती है, इसलिए पैसों का लेन-देन सावधानी से करें। असम्भव सा लगने वाला कार्य भी आप अपने सीनियर और जूनियर की मदद से करने में कामयाब हो जाएंगे।

सिंह सिंह राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर होंगी। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी। जीवनसाथी का हर मोड़ पर सपोर्ट करने के लिए तैयार रहें। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे पैकेज के साथ नई जॉब का ऑफर मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। समाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे।

तुला इस महीने आत्म-सुधार केंद्र स्तर पर है ! आप नई चीजे सीखने या शौक तलाशने के विचारों से भरपूर रहेंगे। कुछ मौज- मस्ती और मनोरंजन के लिए भी तैयार हो जाइए ! लेकिन जबकि व्यापार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, ईमानदार और सतर्क रहें। जिसके चलते आपके भीतर गजब का उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा और आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

धनु सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करने से धनु राशि वालों को जबरदस्त लाभ होगा। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। व्यावसायिक लाभ होगा। नौकरी और कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसकी मदद से भविष्य में किसी बड़ी योजना से जुड़ने का मौका मिलेगा।

कुंभ कुंभ राशि वालों को नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेंगे। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। पिछले निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। धन-दौलत में वृद्धि के योग बनेंगे। परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जा सकते हैं। आपकी रुखे व्यवहार से आपके अपने नाराज होकर दूर जा सकते हैं। इस माह आपके मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी।

वृषभ इस महीने आपके पास नकदी आएगी – लंबे समय से विलंबित धन आखिरकार आ गया है ! वेतनभोगी लोग, रोमांचक विदेशी परियोजनाओं के लिए तैयार हो जाइए जो आपकी प्रतिभा पर प्रकाश डालेंगे। इस दौरान आप मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने से परेशान हो सकते हैं। कारोबार में कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा।

कर्क इस महीने आपकी लव लाइफ को जैकपॉट मिल सकता है ! अंततः कानूनी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अपने बटुए पर नज़र रखें – खर्चे बढ़ सकते हैं। अनावश्यक यात्रा परेशानी का सबब बन सकती है और करीबी परिवार के साथ अनबन हो सकती है। जिसे पूरा करने में मित्रों या फिर स्वजनों की मदद बामुश्किल ही मिल पाएगी।

कन्या इस महीने आत्म-सुधार केंद्र स्तर पर है ! आप नई चीजें सीखने या शौक तलाशने के विचारों से भरपूर रहेंगे। कुछ मौज- मस्ती और मनोरंजन के लिए भी तैयार हो जाइए ! लेकिन जबकि व्यापार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, ईमानदार और सतर्क रहें। माह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कामकाज का बोझ बना रहेगा और उसे समय पर खत्म करने के लिए आपको अतिरिक्त समय देना होगा।

वृश्चिक इस महीने पारिवारिक समय शानदार रहेगा ! आपके घर में प्यार भर जाता है और आपका बटुआ भी थोड़ा भारी लगने लगता है। हालाँकि, अपने स्वास्थ्य पर नज़र रखें – थोड़ी सी अतिरिक्त देखभाल बहुत काम आती है। व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अपने कारोबार के विस्तार की सोच रहे थे तो आपकी यह ख्वाहिश इस माह जरूर पूरी हो जाएगी।

मकर नकदी से भरे महीने के लिए तैयार हो जाइए ! जैसे ही कार्यालय में आपकी कड़ी मेहनत को पहचान मिलेगी, आपका बटुआ आय से भर जाएगा। सहकर्मी आपके चीयरलीडर्स बन जाते हैं, जिससे आपका काम का बोझ कम हो जाता है। आप अपने इष्ट-मित्र की मदद से सभी चुनौतियों को पार करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे।

मीन इस महीने पारिवारिक जीवन में गर्माहट आएगी, लेकिन किसी उपद्रवी से सावधान रहें। नाटक से ऊपर रहें, पारिवारिक मामलों को निजी रखें और धैर्य को अपनी महाशक्ति बनने दें। चीजें जल्द ही सुचारू हो जाएंगी। माह की शुरुआत में आपको अपने करिअर और कारोबार में तमाम तरह की परेशानियों को झेलना पड़ सकता है,लेकिन इस कठिनाई भरे समय में आपके अपने हर पल साथ खड़े रहेंगे।

CCL
Fuelling Sustainable Growth
हमारा प्रयास : हितधारकों, ग्रामीणों एवं श्रमिकों का सर्वांगीण विकास

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम /कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कम्पनी)

दरभंगा हाउस, राँची – 834001 (झारखण्ड)

CentralCoalfieldsLtd CCLRanchi centralcoalfieldsltd Central Coalfields Limited

Postal Registration No! : RN/262/2023 25

संतोष कुमार गंगवार
राज्यपाल, झारखण्ड

गणतंत्र दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार

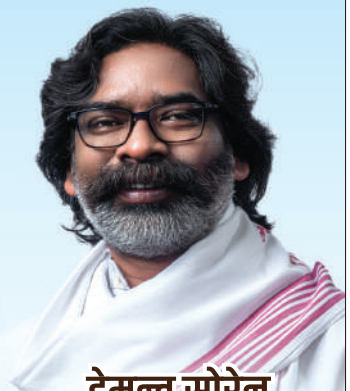

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का यह अवसर है। भारत का लोकतंत्र भारत का गणतांत्रिक अतीत बहुत ही समृद्ध रहा है।
आइए, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम संविधान में निहित आदर्शों और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर देश एवं लोकतंत्र की प्रगति में योगदान दें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार